हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 फरवरी, 1996

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 27 फरवरी, 1996

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 28
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 31
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	(2) 33
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	
चौधरी बंसी लाल द्वारा	(2) 36
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (पुनरारम्भ)	(2) 37
वाक-आउट	(2) 38
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (पुनरारम्भ)	(2) 38
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2) 39
वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना	(2) 41
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(2) 41
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2) 41
बैठक का समय बढ़ाना	(2) 79
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2) 79

मूल्य : 190.00

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol., 1, No. 2, dated the 27th February, 1996.

Read	For	Page	Line
विसंगतियों	विसंगतियां	7	4
सवा	साव	9	3
को	का	12	25
जाती	जातो	25	18
मण्डी	मण्ढी	28	26
अत्याधिक	अत्यधिक	29	35
पहले	पहल	33	11
स्पीकर	स्पकर	34	1
वाले	वामे	34	31
होगा	हागा	35	18
जब	अब	43	20
ज्यादा से ज्यादा	ज्यादा से	45	13
कारगर	कारगार	45	28
लिया	ले लिया	47	27
औद्योगिक	उद्योगिक	48	5
(विघ्न एवं शोर) से पहले 'है।' न पढ़ा जाए		55	13
ठीक	िक	57	23
उन्होंने	उन्हेंने	58	23
कैनाल	खैनाल	66	12
consti-	consi-	67	31
Hospital	Hospit l	78	34
प्लास्टिक	प्लासिटक	82	5
आधे	अ धे	82	15

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 27 फरवरी, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज़, अब सवाल होंगे।

Roads damaged due to floods

***1238. Prof. Chhattar Singh Chauhan:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state the districtwise details of the amount spent on the repairs of the roads damaged due to the floods in the month of September, 1995 in the State from the financial assistance received from the Central Government and from the State Government upto 31-12-95 separately ?

Public Works (B&R) Minister (Chaudhri Amar Singh) : Sir, statement of expenditure district-wise is placed on the table of the House.

Statement

Sr. No.	Name of District	Expenditure incured upto 31-12-95 Central Assistance through State Govt, under Head 2245— (Relief on account of Natural Calamities) (Rs. in lacs)	Central Assistance under Head 3054 (Central) (Rs. in lacs)	State funds under Head—3054 (Non-plan) (Rs. in lacs)
1	2	3	4	5
1.	Ambala	36.31	11.03	
2.	Kurukshetra	108.71	6.55	21.54
3.	Bhiwani	242.18	—	
4.	Mohindergarh	47.19	—	81.20

[Chaudhri Amar Singh]

1	2	3	4	5
5.	Yamunanagar	28.86	—	13.12
6.	Panchkula	127.68	5.27	
7.	Gurgaon	64.03	7.06	97.48
8.	Faridabad	27.26	10.36	
9.	Hisar	217.21	23.57	101.68
10.	Sirsa	27.88	8.50	
11.	Jind	241.27	—	102.28
12.	Kaithal	127.16	—	
13.	Karnal	32.55	12.33	
14.	Panipat	38.02	19.42	142.80
15.	Sonepat	85.60	8.73	
16.	Rohtak	122.40	25.53	111.43
17.	Rewari	22.18	9.73	
	Total :	1596.49	148.08	671.53

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने हर जगह कहा था कि बाढ़ के कारण जो सड़कें टूट चुकी हैं वे जल्दी से जल्दी ठीक कर दी जाएंगी लेकिन आज तक ये सड़कें ठीक नहीं हुई हैं। इन्होंने आज तक किसी भी जिले की सड़कों को ठीक करने के लिए टच नहीं किया है। इन्होंने यह पैसा केवल कागजों में ही खर्च किया हुआ दिखाया है। सारी जनता यह कहती है कि इस पैसे को अमर सिंह और पी०डब्ल्यू० डी०डिपार्टमैंट डकार गया है। भिवानी जिले में जो सड़कें टूटी थीं उनकी भी मुरम्मत नहीं की गई। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भिवानी से जो मुख्य सड़कें रोहतक, महेन्द्रगढ़, नारनौल, जीन्द और कैथल की तरफ से जाती हैं उनकी भी बहुत बुरी हालत है और उनपर अभी तक कार्य शुरु नहीं किया है। कैथल और जींद वाला जो रोड है उस पर 4-5 फुट गहरे गड्ढे हैं लेकिन उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन सारी सड़कों को देखने से ऐसा प्रतीत होता कि जो पैसा खर्च किया हुआ दिखाया है उसको असल में खर्च न करके खुद डकार गए है।

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि मेरे माननीय साथी ने हरा चश्मा लगा रखा है। इनको पता है कि अढाई दिन में जब पिछले दिनों लगातार बारिश आई थी तो उस बाढ़ के कारण सड़कों का व दूसरा कितना नुकसान हुआ था। मेरे साथी इस बात को भी मानेंगे कि भिवानी में इनकी ठोडी तक पानी आ गया था। वहां पर 5–6 फुट पानी आ गया था। मुण्ढाल क्षेत्र जो इनका है वहां पर केवल 235 कि0 मी0 सड़कें हैं और उनमें से 137.2 कि0मी0 रोड डैमेज हुई, उनमें से 118.39 कि0मी0 रोडज रिपेयर हो चुकी हैं और उस पर 73 लाख 75 हजार रुपया खर्च हो चुका है। इसी प्रकार से दादरी में कुल रोड 234.54 कि0मी0 लम्बी है जिसमें से 106.34 कि0मी0 रोड डैमेज हुई और उसमें से 104.14 कि0मी0 रोड रिपेयर की जा चुकी है। उस पर 1 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। भिवानी में कुल रोड 157.19 कि0मी0 लम्बी है इनमें से 64.45 कि0मी0 रोड डैमेज हुई उसमें से 58.59 कि0मी0 रोड रिपेयर हो चुकी है। इस पर 89.86 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। जहां तक मेरे लायक दोस्त ने रोड टूटने की बात और उनकी रिपेयर न कराने की बात कही है उस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां जहां सड़कें पानी के आने के कारण टूटी हैं वहां पर अब हमने सड़कों की 4–4 व 5–5 फुट रेजिंग की है और उनको ठीक कर रहे हैं। मुण्ढाल से जींद–नारनौंद जो सड़क टूट चुकी थी उसकी हमने 5–5 फुट रेजिंग की है और अब वहां पर सारा काम हो चुका है। केवल मैटलिंग का काम रहता है और उसको भी हम 31 मार्च तक कर देंगे। जहां तक कैथल वाली रोड की बात है उस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर सड़क के दोनों तरफ अब भी पानी खड़ा है। इसके बावजूद भी विभाग ने वहां पर रचनात्मक ढंग से जो काम किया है उसको इन्होंने सराहना तो क्या या उलटा इलजाम लगा दिया कि पैसा डकार गए। स्पीकर सर, इनकी शिक्षा ऐसी ही पाठशाला में हुई है जहां डकारने की बात ही होती है। (हंसी) स्पीकर सर, मैं अपने लायक दोस्त को बताना चाहता हूं कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 ने बड़ा रिमार्केबल काम किया है। जहां पर 4–5 फुट पानी खड़ा था वहां पर मिट्टी डाल कर उसको ठीक किया है। ये इस विभाग की सराहना करने के लिए जो बात कहनी चाहिए वह नहीं कह रहे हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं इनको इनके हल्के का भी बता देता हूं कि कुल रोड 235 कि0मी0 है जिसमें से 137.2 किलोमीटर रोड डैमेज हुई उसमें से 118.39 कि0 मी0 रोड की रिपेयर की गई है जिस पर सरकार ने 73.75 लाख रुपये खर्च किए हैं। दादरी में 234.54 कि0 मी0 रोड हैं जिसमें से 106.34 कि0मी0 रोड डैमेज हुई जिसकी रिपेयर पर 1 करोड़ 52 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। भिवानी प्रोपर में 157 कि0मी0 रोडज हैं जिनमें 64.46 कि0मी0 रोड डैमेज हुई है और 58.59 कि0मी0 रोडज की रिपेयर की गई हैं जिस पर 89.86 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा खर्च की गई है।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अभी कुछ आंकड़े दिए हैं और जिलावाईज खर्च का ब्यौरा भी हाउस में रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इनका महकमा दिन रात मेहनत कर के रोडज की रिपेयर में कोई कसर नहीं रख रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यमुनानगर जिले की फिगर की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यमुना नगर जिले में रिपेयर के लिए सबसे कम पैसा दिया गया है। यमुना नगर, करनाल रोड जो गुमथला और गढ़ी बीरबल से जाती है वह सड़क बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। इसी प्रकार से यमुना नगर के साथ लगते जिला कुरुक्षेत्र के एरिया की जो सड़कें हैं उनकी भी हालत काफी खराब है। 4-5 कि0मी0 का टुकड़ा सड़क का बहुत खस्ता हालत में है जो लाडवा से मुस्तफाबाद जाती है। रादौर से मुस्तफाबाद जो रोड जाती है वह भी काफी खराब और बिल्कुल टूट गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन रोड्ज को ये कब तक ठीक करवा देंगे ?

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यमुना नगर जिले के लिए 28.86 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और यह बात ठीक है कि वहां पैसा कम दिया गया है। इस बारे में मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि 17 जिलों में जो बाढ़ आई वह किसी जिले में कम आई और किसी जिले में ज्यादा आई। यमुना नगर जिले में रोहतक और भिवानी जिलों के मुकाबले में बहुत कम बाढ़ आई इसलिए यमुनानगर जिले के लिए 28.85 लाख रुपया दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह भी बताना चाहूंगा कि 31 मार्च, 1996 तक हरियाणा की सभी सड़कों की मुरम्मत कर दी जाएगी।

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की रोडज की रिपेयर नहीं हुई है। किसानों को अपना गन्ना ले जाने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मेरे हल्के में मीरपुर कोरारी से गुलावड़, कुशक रोड से नाई नगला, चवन नगला व अजीजा बाद से बेला और बेला से पिगोड तक की सड़क, बढ़ोली से रहीम पुर सड़क, हसनपुर से सुलतानपुर सड़क, गन्नीका से पैलक और पैलक से सिहोल सड़क, खिरबी से बांसवा और बांसवा से कसाई सड़क, रसूल पुर से गुलावड़ जटोली हसनपुर रोड की हालत खराब है इन सड़कों की मुरम्मत कब तक हो जाएगी ? इस बारे में मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो उन सड़कों के बारे में है जो फ्लड से डैमेजड हुई हैं।

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हालांकि इनका सवाल रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनको कहना चाहूंगा कि अगर ये अपनी प्रेफरेंस देंगे तो इनकी रोडज को ठीक करवा दिया जाएगा।। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का आदेश है कि 31 मार्च, 1996 तक जो रोडेवल रोडज हैं उनकी रिपेयर करवा दी जाएगी।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहूंगी कि सारी सड़कें 12 अगस्त से पहले ही टूट चुकी थीं और बाढ़ आने की वजह से उन सड़कों का और भी बुरा हाल हो गया है। क्या मंत्री जी उन आफिसर्ज की जिम्मेवारी ठहराएंगे जिनकी वजह से सड़कें 12 अगस्त से पहले ही टूट गई थीं।

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने किसी सड़क का नाम नहीं लिया है। इन्होंने यह एक वेग सवाल कर दिया है। हरियाणा में बाढ़ आने से पहले ही सभी रोड्ज ठीक कर दी गई थीं। बाढ़ आने की वजह से 7534 कि0 मी0 सड़कें टूट गई थीं। अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से 80 करोड़ रुपए का सड़कों का नुकसान हुआ था और डिमान्ड 70 करोड़ रुपए की की गई थी जबकि मन्जूरी 31 करोड़ रुपए की हुई। अब चौहान जी कहते हैं पी0डब्ल्यू0 डी0 वाले 40 करोड़ रुपए डकार गए जब कि हमें 31 करोड़ रुपया ही मिला था। इस प्रकार की बातें ये पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं इसलिए इनको इस बात के लिए सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय हमें जो पैसा मिला है उसका बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है और यह सब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।

डा0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र जिले की कौन–कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत नहीं की गई है। अगर इस बारे में इनके पास पूरी लिस्ट न हो तो ये हमें बाद में दे दें ताकि हम पी0डब्ल्यू0डी के आफिसर्ज को भी दिखा सकें कि आपने यह मरम्मत की है और यह रह गई हैं। अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर से कुरुक्षेत्र रोड है उसमें से एक एस0के0 रोड निकलती हैं। उसकी बिल्कुल भी मरम्मत नहीं हुई है।

चौधरी अमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने मेजर रोडज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडज स्टेट हाई–वे और नैशनल हाई–वे पर मरम्मत की है, दूसरे फेज में रुरल एरियाज की सड़कें हैं उनको भी 31 मार्च, 1996 तक ठीक करवा देंगे। अगर इनकी नौलेज में कोई सड़क है वह हमें बता दें हम उसको भी ठीक करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता 108.71 लाख रुपए है जो कि 31 जनवरी तक खर्च कर दी गई है। नैशनल हाई-वे पर 6.55 लाख रुपया और 3.54 लाख रुपया नान प्लान के तहत खर्च किया है। इसके अलावा भी अगर डाक्टर साहब की नौलेज में कोई रोड खराब है उस बारें में हमें बता दें तो हम उसको भी ठीक करवा देंगे।

Demands of Employees

***1243. Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any agreement between the State Government and its Employees Union was arrived during the year 1995-96 in regard to their demands; if so, the details thereof togetherwith the time by which the said agreement will be implemented ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा उठाई गई मांगों पर विचार करने के उपरांत सरकार ने 14 फरवरी, 1996 को कर्मचारियों को कुछ राहत तथा सुविधाएं प्रदान करने बारे घोषणा की है, जिनका विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। सम्बन्धित विभागों को इन घोषणाओं को इस माह के अंत तक लागू करने के आदेश दिये गये हैं।

विवरण

1. तदर्थ आधार पर लगे जिन चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने 31 जनवरी, 1996 को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनकी सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी। इसी प्रकार इस तिथि को 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी दैनिक वेतन भोगी तथा वर्कचार्जड कर्मचारियों को भी नियमित कर दिया जायेगा।

2. फरवरी, 1996 से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 120/- रुपये प्रतिमास अंतरिम राहत दी जाएगी। यह अंतरिम राहत कर्मचारियों को पहले से दी जा रही अंतरिम राहत के अतिरिक्त होगी।

3. सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 1994-95 के लिए बोनस, भारत सरकार द्वारा संशोधित नार्म के अनुसार, अगले वित्त वर्ष में अदा कर दिया जाएगा। बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी तथा बाकी कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

4. राज्य के सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारियों को 1-4-95 से भारत सरकार के संशोधित नार्म अनुसार ग्रेच्यूटी दी जाएगी।

5. सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा फिक्सड चिकित्सा भत्ता फरवरी, 1996 से 100/- रुपये प्रतिमास कर दिया जाएगा। यदि पति-पत्नी दोनों हरियाणा सरकार की सेवा में हैं, तो यह भत्ता दोनों को दिया जाएगा।

6. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोक निर्माण विभागों के कर्मचारियों वेतन नियमित तौर पर अदा किया जाए और इस हेतु दी गई राशि किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न की जाए।

7. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिए जाने वाला वर्दी व धुलाई भत्ता बढ़ाकर फरवरी, 1996 से 75/- रुपये प्रतिमास कर दिया जाएगा।

8. सारे राज्य में आई0सी0डी0एस0 प्रोग्राम के अधीन कार्य करने वाले आंगनवाड़ी वर्करों तथा हैल्परों का वेतन फरवरी, 1996 से क्रमशः 200/- रुपये और 100/- रुपये प्रतिमास बढ़ा दिया जाएगा।

9. फरवरी, 1996 से मकान किराया भत्ता की प्रत्येक स्लैब में 25/- रुपये प्रतिमास की बढ़ौतरी की जाएगी।

10. कर्मचारियों को 10 व 20 साल की सेवा करने के बाद दी जा रही समयबद्ध उच्चतर मानक वेतनमान की स्कीम में रह गई विसंगतियां को दूर किया जाएगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर कटौती के आदेश लागू न करने सम्बंधी हिदायतों की ओर विभागों का ध्यान पुनः दिलाया जाएगा।

11. राज्य वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र देने के लिए अनुरोध किया जाएगा। राज्य वेतन आयोग से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वेतन विसंगतियों के बारे में कर्मचारियों और राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापनों आदि पर उचित रूप से विचार करके अपनी सिफारिशें दें।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार को स्टेट पे कमीशन की रिपोर्ट कब तक मिलने की संभावना है और यह रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसको कब तक लागू कर देगी? इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, सरकार समय समय पर ईम्पलाइज को जो भी रिलीफ देने की घोषणा करती है तो वह रिलीफ कई बार ईम्पलाइज को तो दे दिया जाता है लेकिन पैंशनर्ज को वह रिलीफ देने से बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। उनको यह रिलीफ 6-6 महीने के बाद मिलती है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जब भी ये अन्य दूसरे ईम्पलाइज को जो भी रिलीफ देंगे तो उसी के साथ साथ पैंशनर्ज को भी यह रिलीफ देंगे? इसी तरह से आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को यह मालूम है कि हरियाणा प्रदेश के स्कूल अध्यापक दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर अन्दोलन कर रहे हैं। उनकी ऐसोसियेशन के दो अध्यापक मि० राम पाल दहिया जो कि ऐसोसिएशन के प्रैजीडैन्ट भी हैं और दूसरे मि० तहलान क्रमशः 46 और 32 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं लेकिन सरकार ने उनसे आज तक भी कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी है। क्या मुख्य मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगे कि सरकार उनसे भी जल्दी ही बातचीत करेगी और जो उनकी जायज मांगे हैं उनको सरकार मान लेगी। अध्यक्ष महोदय, उनकी मुख्य मांगें हैं कि सरकार चट्टोपध्याय रिपोर्ट को लागू करें तो मुख्य मंत्री जी से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार चट्टोपध्याय रिपोर्ट लागू कर देगी ताकि अध्यापकों को इंसाफ मिल सके।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, बेरी साहब ने सबसे पहले पूछा कि पे कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हो जाएगी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने उनसे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा हुआ है और जैसे ही वह रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, हम उसको एक महीने के अंदर अंदर ऐग्जामिन करके लागू कर देंगे। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि हमने ईम्पलाईज को कई राहतें दी हैं। समय समय पर कर्मचारियों ने जब भी हमारे

[चौधरी भजन लाल]

सामने अपनी मांगें रखी हैं तभी हमने उनको कई प्रकार की राहतें दी हैं । हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है । अगर मैं यह कहूं कि अधिकारी और कर्मचारी हरियाणा प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं तो गलत नहीं होगा । जब भी उन्होंने हमारे सामने अपनी मांगें रखी हैं हमने हमेशा उनके साथ अच्छा ही बर्ताव किया है । जो राहतें मेरी सरकार ने उनको दी हैं ऐसी आज तक किसी सरकार ने उनको नहीं दी हैं । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने उनको जो राहतें दी हैं उनमें तदर्थ आधार पर लगे जिन तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों ने 31 जनवरी, 1996 को दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनकी सेवाएं नियमित कर दी जाएंगी । इसी प्रकार इस तिथि को जिनकी सेवा पांच वर्ष की पूरी हो जाएगी । उन सभी डेली वेजिज और ऐडहाक कर्मचारियों को भी हमने पक्का करने का फैसला किया है ।

श्री अध्यक्ष : आप यह भी बताएं कि जिन लोगों को पहले तीन तीन या छः छः महीने के लिए लगा लिया गया था और फिर बाद में उनको निकाल दिया गया था तथा फिर उनको लगा लिया था और उनको लगे हुए भी कई साल हो गये हैं क्या वे भी इसमें शामिल हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कायदे में तो दो साल और पांच साल की सर्विस ही होनी चाहिए लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि जिन कर्मचारियों को पांच साल से ज्यादा लगे हुए हो गये हैं और यदि उनको एक दिन का ब्रेक सर्विस में लग गया है तो उनके केसिज के बारे में भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोशिश करेंगे कि उनको भी हम लगा लें ।

अध्यक्ष महोदय, हमने कर्मचारियों को जो राहत राशि दी है उससे सरकारी खजाने पर 137 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा । हमने एक साथ बहुत सारी एनाउंसमैंटस की हैं । इन्होंने अपने सवाल में जैसे कह दिया कि कुछ कर्मचारी अभी भी दिल्ली में बैठे हैं । अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक तौर पर कुछ राजनीतिक लोग उनको गुमराह करते हैं । सभी ग्रुपों ने अनकंडीशनली अपनी स्ट्राइक विदड्रा करने के लिए लिख कर दिया है ।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी तारीख को उन्होंने लिख कर दिया था कि हम अपनी स्ट्राइक विदड्रा करते हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 9-1-96 को लिख कर दिया है ।

डा0 राम प्रकाश : उसमें हस्ताक्षर किस-किस के हैं ?

चौधरी भजन लाल : उसमें श्री एस0डी0 कपूर, श्री पी0एस0 सांगवान, श्री बलदेव सिंह और श्री एम0एल0 सहगल के हस्ताक्षर हैं। अध्यक्ष महोदय, स्टेट में सवा तीन लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं। साव लाख के करीब बोर्ड और कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं उनको भी हमने राहत राशि दी है। इससे बढ़िया काम कोई और हो नहीं सकता। आप जानते हैं कि बहुत भयंकर बाढ़ स्टेट में आई थी उन हालात में भी हमने कर्मचारियों की मांगें मानकर उनके साथ पूरी हमदर्दी दिखाई है और कर्मचारियों से भी हम उम्मीद करते हैं कि वे स्टेट के भले के लिए निष्ठा और लगन से काम करेंगे।

Criminal cases under Trial in the Courts

*1253. **Shri Ram Bhajan Aggarwal** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise total number of cases of murder/theft/robbery/rape are under trial in various Courts in the State during the years 1994-95 and 1995-96; and

(b) the number of cases out of those as referred to in part (a) above have been decided so far ?

मुख्य मन्त्री (चौ0 भजन लाल) : सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

[चौधरी भजन लाल]

सूचना

भाग (क)

जिला	हत्या			चोरी			लूट			बलात्कार		
	94	95	96 (31-1-96)	94	95	96 (31-1-96)	94	95	96 (31-1-96)	94	95	96 (31-1-96)
पंचकूला	—	10	—	42	46	1	1	—	—	5	9	1
अम्बाला	16	16	—	71	87	1	3	4	—	4	6	—
यमुनानगर	21	17	—	194	150	3	7	6	—	16	10	—
कुरुक्षेत्र	16	15	—	112	99	—	5	5	—	5	15	—
कैथल	12	15	—	32	42	—	7	9	1	4	7	—
हिसार	50	40	1	223	103	11	9	7	—	6	17	2
सिरसा	22	22	—	84	43	2	4	5	—	6	7	—
भिवानी	14	17	—	86	65	2	8	6	—	6	18	—
जींन्द	21	9	—	91	85	1	1	3	—	5	9	—
गुड़गांव	39	56	—	269	235	12	36	12	—	20	15	—
फरीदाबाद	43	40	—	268	315	15	29	23	—	24	36	—
नारनौल	9	15	—	32	37	3	3	2	—	4	5	—
रिवाड़ी	14	21	—	71	74	1	5	7	—	5	12	1
रोहतक	55	42	—	175	148	3	18	11	—	19	20	—
सोनीपत	48	31	—	109	118	—	16	26	—	11	10	—
करनाल	17	29	—	174	160	3	2	1	—	20	24	—
पानीपत	33	28	—	174	118	—	9	6	—	13	18	—

भाग (ख)

जिला	हत्या			चोरी			लूट			बलात्कार		
	94	95	96 (31-1-96)	94	95	96 (31-1-96)	94	95	96 (31-1-96)	94	95	96 (31-1-96)
पंचकूला	—	—	—	16	15	—	1	—	—	—	—	—
अम्बाला	12	2	—	55	15	—	1	1	—	8	—	—
यमुनानगर	—	1	—	14	5	—	—	—	—	1	1	—
कुरुक्षेत्र	3	1	—	14	10	—	—	—	—	13	1	—
कैथल	8	1	—	11	—	—	—	—	—	5	1	—
हिसार	10	6	—	28	7	—	1	—	—	5	3	—
सिरसा	6	—	—	13	4	—	—	—	—	1	—	—
भिवानी	14	1	—	6	4	—	—	—	—	1	—	—
जीन्द	14	2	—	12	3	—	—	—	—	6	1	—
गुड़गांव	1	—	—	23	2	—	—	—	—	—	—	—
फरीदाबाद	2	5	—	41	26	—	—	—	—	2	4	—
नारनौल	9	1	—	9	—	—	—	—	—	1	1	—
रिवाड़ी	3	—	—	21	3	—	—	—	—	1	1	—
रोहतक	7	3	—	19	11	—	2	—	—	3	1	—
सोनीपत	3	3	—	34	2	—	1	—	—	2	—	—
करनाल	10	1	—	37	8	—	—	—	—	12	4	—
पानीपत	1	1	—	20	2	—	—	—	—	1	2	—

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बलात्कार और हत्याओं की जो संख्या बढ़ी है वह खास तौर से भिवानी और हिसार जिले में बढ़ी है, हिसार जबकि मुख्य मंत्री जी का अपना जिला है वहां बलात्कार की घटनाएं तीन गुनी हो गई हैं। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि ला एन्ड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और कहते हैं कि स्त्री जाति का पूरा सम्मान किया जाएगा तो मैं जानना चाहूंगा कि बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ गई हैं ? क्या सरकार इसके लिए कोई विवरण देगी। दूसरे अध्यक्ष महोदय, स्त्री जाति के साथ स्टेट के अन्दर अपमान हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। कोई दिन भी ऐसा नहीं है जब ऐसे केसिज नहीं होते। एक दो जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बलात्कार के केस हो रहे हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम भजन जी बहुत काबिल मैंबर हैं। इन्होंने भिवानी और हिसार का जिक्र किया कि वहां पर बलात्कार की कुछ घटनाएं घटीं। अध्यक्ष महोदय, घटना तो घट सकती है मैं इससे इन्कार नहीं करता। राष्ट्रपति होते हुए कैनेडी जैसे आदमी को भी मार दिया था। लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि ऐसी घटनाओं के बारे में पूरी कार्यवाही करे। मैं बताना चाहता हूं कि भिवानी जिले में बलात्कार की 15 घटनाएं हुईं और 15 लोगों का चालान कर दिया है और वे गिरफ्तार कर लिए हैं। जहां तक हिसार का ताल्लुक है मैं कहता हूं कि हर जिले में घटना घटती है और उस बारे में सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जहां कहीं भी महिलाओं के साथ ज्यादती होती है और उसके बारे में हमने आदेश दिए हुए हैं कि फौरन वहां डी0एस0पी0 रैंक का अफसर जाए और फौरी तौर पर कार्यवाही करे। इसलिए सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। हमने महिलाओं का आदर और सम्मान करने के लिए कई स्कीमें चलाई हैं जैसे अपनी बेटी अपना धन की स्कीम है। लड़कियों की बी0ए0 तक और आई0टी0आई0 की शिक्षा फ्री कर रखी है। पंचायती राज में भी हमने महिलाओं का पूरा सम्मान किया है। हमने इनको सम्मान देने की हर तरह से पूरी कोशिश की है। जिस प्रदेश में नारी का सम्मान नहीं होता वह प्रदेश कैसा। इसलिए हमारी भरसक कोशिश रहती है कि कहीं भी किसी देवी के साथ जुल्म या अन्याय न हो। इस बारे में सरकार की तरफ से कहीं भी कोई कोताही नहीं रही। आप जानते हैं कि घटना तो कहीं भी घट सकती है लेकिन जो सरकार का कर्तव्य बनता है उसे निभाया है।

Illegal Possession of the land of Municipal Corporation of Faridabad.

***1259. Shri Azmat Khan :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) whether any case of illegal possession on the land of Municipal Corporation, Faridabad by some persons has come to the notice of the Government; if so, the details thereof; and

(b) the steps, if any taken or proposed to be taken to get the land referred to in part (a) above vacated therefrom ?

Minister of State for Local Government (Chaudhri Dharambir Gauba) :

(a) Yes, Sir, Land measuring around 250 acres scattered in 12 villages has been in illegal possession for the last 8 to 10 years. Another 250 acres of Shamlat Deh land in village Anangpur is also in the possession of various persons having purchased their shares from village proprietors.

(b) Regarding illegal possession in the said 12 villages, 104 eject-ment cases are pending in the Courts of the Sub Divisional Officers (Civil), Ballabhgarh and Sub Divisional Officer (Civil) Faridabad, enjoying powers of Collector under the Public Premises Act. Regarding illegal possession in Village Anangpur after having lost the case in lower courts, RSA No. 1936 of 1987 filed by Municipal Corporation, Faridabad and CWP No. 12868 of 1992 filed by Village Proprietors are pending in the Hon'ble High Court and stay order granted by the High Court in CWP is also operative. On the Misc. Application moved by the Corporation for early hearings in these cases, both the cases have been argued on 13th and 14th Feb., 1996 and the orders on the same are still awaited. Accordingly, action will be taken after the verdict of the Hon'ble High Court is received.

10.00 बजे ।

श्री अजमत खां : स्पीकर साहब, मैं इस सवाल की रिटन रिप्लाई से सन्तुष्ट हूं ।

Visit to Foreign Countries by the Officers of the State Government

*1239. **Shri Kitab Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the names and designations of the officers of the State Government who undertook the foreign tour during the period from 1991 to 1996 togetherwith the purpose of their visit alongwith the amount of expenditure incurred on the said visit.

श्री अध्यक्ष : इस सवाल को एक्सटैंशन मांगी गई है क्योंकि ग्रांट कर दी गई है ।

श्री किताब सिंह : स्पीकर साहब, यह सवाल किस दिन लगेगा, वह दिन तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष : आपको रिटन रिप्लाई चला जाएगा। इस समय मैं आपको इसके बारे में एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि यह कौन से दिन लगेगा। इस सवाल के बारे में गवर्नमैंट की ओर से जो रिक्वैस्ट आई है वह इस प्रकार है :—

D.O.No. 62/8/96-6GSI

"Bhajan Lal

Chief Minister, Haryana,
Chandigarh

Dated the 26th Feb., 1996

My Dear Ishwar Singh ji,

The reply to starred Assembly Question No. 1239 appearing in the list of question for 27-2-96 in the name of Chief Minister, Haryana is not ready as the relevant information is being collected from all the departments of Haryana Government including Boards and Corporations which is a time consuming work. The information will be furnished as soon as it is ready. It will need atleast four weeks to collect the information.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Bhajan Lal)

Shri Ishwar Singh,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh."

Accidents occurred in the State

***1262. Sathi Lehri Singh** : Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the depotwise number of buses of Haryana Roadways met with accidents during the last six months ;

(b) the number of persons died/injured in the accidents as referred to in part (a) above;

(c) the total damage in terms of rupees caused to the State Transport in the accidents as referred to in part (a) above;

(d) the amount of compensation, if any, paid by the Government to the persons injured and the family of the deceased involved in the said accidents; and

(e) the action taken or proposed to be taken to prevent such accidents in future ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल शाह):

(क) से (घ) विवरणी विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाये गए हैं :—

1. सभी चालकों का दृष्टि परीक्षण करवाया जा रहा है जिन चालकों की दृष्टि कमजोर हैं उन्हें चश्में निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे है। जिन चालकों की दृष्टि चश्मा लगाने से भी ठीक नहीं हो पाती है उन्हें वैकल्पिक डियूटी दी जा रही है।

2. चालक प्रशिक्षण स्कूल, मूरथल में सभी चालकों के लिए ग्रुपों में कड़ी प्रशिक्षण सेवा लागू की गई।

3. वाहनों को तेज गति से चलाने पर नियंत्रण रखने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में स्पीडोमीटर कार्य कर रहे हैं। मुख्य बस स्टैण्डों पर लगाने हेतु टाईम पंचिंग मशीनें प्राप्त की जा रही हैं ताकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में वाहन द्वारा लिए गए समय की जांच की जा सके। इसके अतिरिक्त डीजल की खपत में सुधार लाने हेतु समय समय पर नियमित रुप से चालकों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। डीजल की खपत में सुधार से वाहनों की गति पर नियंत्रण सुनिश्चित है।

4. चालकों के चयन की प्रणाली भी कड़ी कर दी गई है। प्रत्याशियों का विस्तृत चालक टैस्ट लिया जाता है जिसमें भिन्न-भिन्न कार्य साधन युक्तियां शामिल हैं। चालक द्वारा नशीली वस्तुओं का सेवन रोकने हेतु कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। चालक ने कितनी शराब पी हुई है, उसे एकदम चैक करने हेतु "ब्रैथ ऐनेलाईजर" प्राप्त किए जा रहे हैं। डियूटी पर शराब पीये हुए पाए जाने वाले चालकों को कड़ी सजा दी जा रही हैं।

5. बसों की रख रखाव में सुधार सुनिश्चित करने हेतु एक अभियान चलाया गया है ताकि बसों में नुक्स के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं में कमी हो।

6. महा प्रबन्धक नियमित रुप से चालकों को वाहनों को सुरक्षा पूर्वक चलाने की प्रेरणा देने हेतु सम्बोधित करते हैं।

7. मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल के निर्णय के आधार पर दोषी पाए जाने वाले चालकों के विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 7 के तहत कार्यवाही की जाती है।

विवरणी

Statement showing the Accidents involving Haryana Roadways Buses which occurrd in the State from 1-8-1995 to 31-1-1996

Sr. No.	Depot	No. of buses involved in accidents	No. of persons died	No. of persons injured	Amount of damage to buses (In Rupees)	Amount of compensation paid to persons injured and family of the deceased.
1	2	3	4	5	6	7
		(a)	(b)		(c)	(d)
1.	Ambala	20	5	13	88,843.66	
2.	Bhiwani	15	12	4	86,939.00	So far no claims have been received in relation to these accidents.
3.	Chandigarh	20	24	25	2,31,975.60	
4.	Dadri	14	10	7	42,163.00	
5.	Delhi	19	7	5	27,485.85	
6.	Fatehabad	21	10	15	58,871.00	
7.	Faridabad	26	9	10	1,37,425.95	
8.	Gurgaon	16	8	15	45,267.00	
9.	Hisar	17	7	3	34,361.00	

1	2	3	4	5	6	7
10.	Jind	26	7	9	2,57,803.50	
11.	Karnal	10	1	2	28,071.81	
12.	Kurukshetra	38	8	17	2,78,590.00	
13.	Kaithal	19	12	47	1,80,000.00	
14.	Panipat	8	—	16	1,09,906.00	
15.	Rohtak	16	17	13	4,82,954.60	
16.	Rewari	16	5	16	50,433.40	
17.	Sirsa	18	6	5	10,175.20	
18.	Sonipat	19	13	17	2,25,472.90	
19.	Yamunanagar	30	11	60	6,33,693.11	
	Total	368	172	299	30,10,432.58	

साथी लहरी सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बस एक्सीडैंटस की जो स्टेटमैंट दी है उसके अनुसार 360 बसिज के एक्सीडैंटस हुए है और उनमें से यमुना नगर डिपो की 30 बसिज का नुकसान हुआ है और वह लगभग 6.34 लाख रुपए का हुआ है। स्पीकर साहब, एक्सीडैंटस के कारण बसिज का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में तो मंत्री जी ने जवाब दे दिया है लेकिन इनसे मैं यह जानना चाहता हूं कि उन एक्सीडैंट्स में मरने वाले लोगों को कम्पनसेशन के तौर पर कितना पैसा दिया गया। जो आदमी उस समय किसी ब्याह शादी में जा रहे थे और एक्सीडैंट से उनकी आन दि स्पोट डैथ हो गई क्या ऐसे मौकों पर मरने वालों के वारिसों को आन दि स्पोट कोई पैसा कम्पनसेशन के तौर पर विभाग का देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एक्सीडैंट्स होने के बाद मरने वालों और घायल हुए लोगों को डिपार्टमैंट वाले खुद हॉस्पीटल में ले जाते हैं और क्या विभाग वाले उनकी खुद पैरवी करते हैं ? इन एक्सीडैंटस की वजह से बसों का जो इतना अधिक नुकसान हुआ है क्या उसके लिए किसी की कोई जिम्मेवारी फिक्स की गई कि आया वह एक्सीडैंट बस में कोई खराबी के कारण हुआ या ड्राईवर की लापरवाही के कारण हुआ। किस किस के खिलाफ जी0एम0 ने कार्यवाही की यह भी बताएं। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन जिन जी0 एम0 के डिपोज की बसों के अधिक एक्सीडैंट्स हुए हैं सरकार ने उन जी0 एम0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की और उनको क्या सजा दी ?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, इन्होंने मूल प्रश्न में यह पूछा है कि पिछले छः महीने में कितने क्लेम एक्सीडैंटस के हुए हैं। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्लेम मोटर एक्सीडैंटस क्लेम्ज ट्रिब्यूनल में जाते हैं। वहां पर फैसला होने पर लगभग एक साल का समय लग जाता है। इसलिए मूल प्रश्न में जो पिछले छः महीने का जिक्र किया है उसका तो कोई क्लेम नहीं दिया गया। जहां तक मौके पर सरकार द्वारा या डी0 सी0 द्वारा राहत देने की घोषणा की जाती है तो वह पैसा उनको जल्दी दे दिया जाता है और बाद में वह पैसा जो ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें दिया जाना होता है, में से काट लिया जाता है। जिन चालकों के कारण एक्सीडैंट होते हैं उनके विरुद्ध रूल 7 के तहत कार्यवाही करते हैं। जब एक्सीडैंट होता है तो हमारे संबंधित अधिकारी और पुलिस विभाग उनको संभालता है और बाकायदा फर्स्ट एड और इलाज की सुविधा मुहैया करवाई जाती है।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, क्या यह तथ्य सही नहीं है कि वाहनों के ज्यादातर एक्सीडैंट बसों में टायर ठीक न होने के कारण और ब्रेक ठीक न होने के कारण होते हैं ?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, जो दुर्घटनाएं होती हैं व दोनों तरफ से ही होती हैं। (विघ्न) हमारे चालकों की लापरवाही के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं और सामने से आ रहे वाहन की गलती के कारण भी होती हैं। बसों के रखरखाव

की तरफ पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। बसों की ठीक समय पर सर्विस की जा रही है। किसी बस की सर्विस के एक सप्ताह के अन्दर यदि तकनीकी खराबी के कारण एक्सीडेंट होता है तो वर्कस मैनेजर और संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्रीमती चन्द्रावती : बिल्कुल भी टाईम पर बसों की सर्विस नहीं होती।

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अधिकतर एक्सीडेंटस ओवर स्पीड के कारण होते हैं। क्या इसको रोकने के लिए कोई पग उठाये गए हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि कुछ एक्सीडेंट इसलिए भी होते हैं कि सड़कें कम चौड़ी हैं, क्या इस तरफ भी सरकार ध्यान देगी और सड़कों को चौड़ा कराएंगी ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हों?

श्री बलबीर पाल शाह : यह बात सही है कि बहुत से एक्सीडेंट ओवर स्पीड के कारण होते हैं। हमने बसों की स्पीड को रोकने के लिए गवर्नर फिट किए हुए हैं लेकिन कई चालक इसको टैम्पर कर देते हैं। यदि हमारे नोटिस में ऐसी बात आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है। यह भी तथ्य सही है कि कुछ दुर्घटनाएं सड़कों के कम चौड़ा होने के कारण भी होती हैं।

श्री अनीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया था कि किसी दुर्घटना के बाद कई बार डी0सी0 साहब की तरफ से कोई राहत की एनाउसमेंट की जाती है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के आदेश हैं कि जहां एक्सीडेंट में कोई मौत होगी 15 हजार रुपया फौरन दिया जाएगा लेकिन डी0सी0 के कहने पर दिये जाने का क्या कोई स्टैंडिंग आर्डर है कि मौके पर 15 हजार रुपये का रिलीफ दिया जाएगा? दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिनका क्लेम मंजूर होता है क्या उसका पैसा ड्राईवर से वसूल किया जाता है या उसको सरकार वहन करती है?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर सर, 15 हजार रुपये उस केस में दिये जाते हैं जिसमें एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाए। इन्जरीज भी एक्सीडेंटस में होती हैं, ऐसे एक्सीडेंटस में इन्जरीज के लिए 2 हजार या 5 हजार जितना भी पैसा डी0सी0 मन्जूर करता है वह पैसा डिपार्टमैंट दे देता है। जहां तक पैसा ड्राईवर से रिकवर करने का प्रश्न है, अगर एक्सीडेंट में ड्राईवर का कसूर पाया जाए तो ड्राईवर पर भी रिकवरी डाली जाती है लेकिन सभी केसों में ऐसा नहीं होता।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज की जो बसें हरियाणा स्टेट में या दूसरी स्टेटस में चलती हैं उनमें पहले शिकायत पुस्तिका होती थी जिसमें सवारी कोई शिकायत दर्ज कर सकती थी परन्तु अब वह शिकायत

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
पुस्तिका बस में होने की बजाय बस स्टैंडज पर बुकिंग कांउटर पर रखी हुई होती है और वहां पर शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है जो कि गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि क्या वे ऐसा प्रयास करेंगे कि शिकायत पुस्तिका बस स्टैंडज के बुकिंग कांउटर की बजाय बसों के अन्दर रखी जाए ताकि शिकायत कर्ता शिकायत दर्ज कर सकें।

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, पहले ऐसा ही प्रावधान था लेकिन आम शिकायत थी कि कण्डक्टर कम्पलेंट बुक मांगने पर कई बार नहीं देते थे जिससे कम्पलेंट दर्ज नहीं हो पाती थी इसलिए ऐसा प्रावधान करना पड़ा है। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि शिकायत पुस्तिका बस के अन्दर रखी जाए तो फिर से यह तजुर्बा कर लेते हैं।

श्री अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी बहुत काबिल हैं, शायद इनको भी इस बात का पता होगा कि आज हरियाणा में लोग उतना ट्रकों से नहीं डरते जितना की हरियाणा रोडवेज की बसों से बचने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, क्या हमारे अन्दर ऐसी कोई कमी है जिससे बसों के कारण ज्यादा एक्सीडैंट होते हैं। अध्यक्ष महोदय मैं यह बात मन्त्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि उतने एक्सीडैंट्स ट्रकों से नहीं होते जितने बसों से होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे ड्राईवरज को कोई ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध करेंगे तथा स्पीड को कण्ट्रोल करने के लिए इन्तजाम करेंगे। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ड्राईवर्ज गवर्नर्ज को तोड़ देते हैं, क्या गवर्नर टूटा हुआ मिलने पर ड्राईवर के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलबीर पाल शाह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि गवर्नर टूटा हुआ पाए जाने पर ड्राईवर के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाती है। जहां तक एक्सीडैंट रेशो का प्रश्न है, मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा रोडवेज का एक लाख किलोमीटर के पीछे एक्सीडैंट रेशो 0.19 है जो कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में काफी कम है। एक्सीडैंट रेशो पैप्सु रोडवेज की 0.29, चण्डीगढ़ ट्रांसपोर्ट बसों की 0.53, दिल्ली की 0.61, राजस्थान की 0.24 है। हमारी एक्सीडैंट रेशो दूसरी स्टेटों की रोडवेज से काफी कम है। इस वर्ष हमारी एक्सीडैंट रेशो 0.19 है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडैंट रेशो और भी कम हो। स्पीड को चैक करके भी इस रेशो को कम करने की कोशिश करेंगे। ड्राईवरज के लिए मुरथल में एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला है ताकि ड्राईवरज को सेफटी के बारे में समझाया जा सके। अगले साल हम कोशिश करेंगे कि एक्सीडैंट रेशो और कम हो।

Damage caused due to floods

***1237. Prof. Chhattar Singh Chauhan :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the districtwise extent of loss in terms of rupees, if any, caused to the crops/houses/shops in the State due to the floods in the months of August-September, 1995;

(b) whether any compensation has been given to the farmers/owners of the houses and shops, if so, the districtwise details thereof ;

(c) whether financial assistance has been received from the Central Government for providing relief to the flood affected people of the State; if so, the amount thereof ;

(d) the districtwise details of the compensation given to the flood affected people out of the Central assistance as referred to in part (c) above; and

(e) whether there is any proposal under consideraion of the Government to avoid such occurrence in the State in future ?

राजस्व मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह दांगी) :

(क) राज्य में अगस्त-सितम्बर 1995 में बाढ़ से फसलों, मकानों व दुकानों को हुए नुकसान का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है (अनुबन्ध क) । फसलों का अनुमानित नुकसान 1591 करोड़ रुपये है। मकानों व दुकानों के मालिकों को हुए नुकसान का अनुमान लगाना कठिन है लेकिन उन्हें सरकार की निर्धारित दरों पर मुआवजा प्रदान किया गया है ।

(ख) किसानों तथा मकानों व दुकानों के मालिकों को 20.2.96 तक दिए गये मुआवजे का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है (अनुबन्ध ख)

(ग) हां । केन्द्रीय सरकार ने 570 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता, जिसमें 39.41 करोड़ रूपये ग्रान्ट के रूप में 300 करोड़ रूपये ऋण के रूप में तथा बाकी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत अतिरिक्त अंशदान के रूप में, स्वीकृत की है ।

(घ) 206.52 करोड़ रूपये की राशि उपायुक्तों को बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता तथा मुआवजा प्रदान करने के लिए स्वीकृत की गई है । बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक कार्यों की मुरम्मत हेतु विभिन्न विभागों को 157.76 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गये हैं । 50 करोड़ रूपये की राशि जून 1996 से पूर्व अल्पकालिक बाढ़ नियन्त्रण कार्यों

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

के लिए अंकित कर दी गई है । इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों की मुरम्मत करवाई गई है । इस बारे एक विस्तृत स्टेटमेन्ट सदन के पटल पर रखी जाती है (अनुबन्ध ग) ।

(ङ) राज्य सरकार बाढ़ की भविष्य में रोकथाम के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है जिसके लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन सिंचाई व संसदीय कार्य मन्त्री की अध्यक्षता में किया गया है । इस समिति की अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं । समिति द्वारा 31.3.96 तक अपनी सिफारिशें देने की सम्भावना है ।

ANNEXURE 'A'

Statement showing the damage to Crops, houses and Shops by floods during 1995.

Sr. No.	District	Damage to crops (Area in acres)	No. of houses damaged	No. of Shops damaged
1	2	3	4	5
1.	Ambala (including Panchkula)	15,830	17,682	—
2.	Yamuna Nagar	3,168	7,863	—
3.	Kurukshetra	11,500	4,220	—
4.	Kaithal	61,732	12,980	—
5.	Rewari	86,090	8,300	—
6.	Gurgaon	21,730	5,260	—
7.	Faridabad	50,000	3,000	—
8.	Mahendergarh	—	2,849	—
9.	Hisar	3,88,887	29,935	Not available
10.	Sirsa	25,000	4,043	—
11.	Bhiwani	1,37,000	13,893	3,000
12.	Jind	4,37,500	35,529	—
13.	Rohtak	4,54,733	55,918	6,070
14.	Sonipat	65,750	7,231	—
15.	Panipat	7,000	3,150	—
16.	Karnal	20,000	10,225	—
	Total	17,85,920	2,22,078	9,070

ANNEXURE 'B'

Statement showing the Compensation paid to farmers/owners of Houses/Shops, as on 20-2-96.

Sr. No.	District	Compensation paid for (Rs. in lacs) Crops	Houses	Shops	Total
1	2	3	4	5	6
1.	Ambala	41.57	403.77	—	445.34
2.	Kurukshetra	28.14	191·48	—	219.62
3.	Yamuna Nagar	1.72	148.07	—	149.79
4.	Kaithal	363.08	419.19	—	782.27
5.	Panchkula	0.11	145.52	—	145.63
6.	Rewari	10.32	195.66	—	205.98
7.	Gurgaon	72.50	71.39	—	143.89
8.	Faridabad	189.00	89.25	—	278.25
9	Mahendergarh	—	16.70	—	16.70
10.	Hisar	1408.68	1123.09	14.43	2546.20
11.	Sirsa	65.86	213.73	—	279.59
12.	Bhiwani	420.97	977.00	246.00	1643.97
13.	Jind	977.48	1183.00	—	2160.48
14.	Rohtak	1163.45	1243.56	495.00	2902.01
15.	Sonipat	400.00	226.93	—	626.93
16.	Panipat	14.00	148.25	—	162.25
17.	Karnal	17.17	174.26	—	191.43
	Total	5174.05	6970.85	755.43	12,900.33

ANNEXURE 'C'

Statement showing the funds alloted for flood relief measures to Deputy Commissioners/Departments.

Sr. No.	District	Allotment made (Rs. in lacs)
1.	Ambala	622.05
2.	Yamunanagar	165.68
3.	Kurukshetra	278.80
4.	Kaithal	1390.89
5.	Panchkula	129.00
6.	Rewari	472.70
7.	Gurgaon	302.02

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

Sr. No.	District	Allotment made
8.	Faridabad	310.60
9.	Mahendergarh	44.14
10.	Hisar	3434.89
11.	Sirsa	410.93
12.	Bhiwani	3028.75
13.	Jind	3323.00
14.	Rohtak	4993.70
15.	Sonipat	1077.36
16.	Panipat	378.74
17.	Karnal	290.33
	Total	20652.58

Funds allocated to departments

Sr. No.	Name of Department	Funds allocated (Rs. in lacs)
1.	Irrigation	3875.00
2.	Health	265.00
3.	Public Health	1810.00
4.	P.W.D. (B&R)	5947.00
5.	Animal Husbandry	529.00
6.	H.S.E.B.	1500.00
7.	Local Govt.	964.00
8.	Higher Education	36.00
9.	Rural Development	600.00
10.	HUDA	250.00
	Total	15776.00

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जो मुआवजा दिया गया है उस बारे में हर जिले के हर गांव में लोगों में बहुत रोष है कि असल में जिनका जितना नुकसान हुआ है उनको उतना मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे दोबारा से सर्वे करवा कर लोगों को सही मुआवजा देने पर विचार करेंगे।

दूसरे, आज तक हरियाणा सरकार कहती आई है कि हमें बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 570 करोड़ रुपए की ग्रांट केन्द्रीय सरकार से मिली है लेकिन गवर्नर एड्रेस में

गवर्नर साहब ने माना है कि इसमें यह कर्जा मिला है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इस कर्जे को कितनी किश्तों में वापिस किया जाएगा और इस पर कितना ब्याज लगेगा? इस कर्जे की टर्म एंड कंडिशन क्या है। अध्यक्ष महोदय, आज तक इन्होंने हरियाणा के लोगों को गुमराह किया है कि हमें केन्द्रीय सरकार से एड मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप लोगों को गुमराह न करें, वरना लोग आपको माफ नहीं करेंगे।

तीसरे, बाढ़ से हुए नुक्सान का मुआवजा देने के बारे में जो लिस्ट सदन की पटल पर रखी है उसके अनुसार मंत्री जी राहत देने पर भी मुख्यमंत्री जी से डर गए हैं क्योंकि इन्होंने हिसार जिले को बहुत ज्यादा राहत दे दी है जबकि वहां पर इतना नुक्सान नहीं हुआ है। यह जो हिसार जिले को राहत दी गई है, वह राहत है या पोलीटीकल राहत है।

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इनका पहला सवाल है कि क्या मुआवजा ठीक ढंग से बांटा गया है। अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने जितनी स्पीड से काम किया है वह लोगों को राहत देने के लिए किया है। यह रिकार्ड की बात है। जितना मुआवजा जिस ढंग से आज की सरकार ने दिया है वह पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इन्होंने एक सवाल यह भी किया है कि कुछ लोगों को ठीक ढंग से मुआवजा नहीं मिला है यह बात इनकी मानने की है कि दो चार परसैंट इस काम में कमियां रह ही जाती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में हमारी सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। इसके लिए हमने अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर समय-समय पर फील्ड में चैक करने के लिए भेजी है। उनकी जो रिपोर्टस आयी हैं उन के हिसाब से अधिकारिक लेवल पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं बरती गयी है। हो सकता है कि इसमें लोगों की आपस की खींचतान की वजह से और पंचायतों के चुनावों की वजह से उनमें आपस में कुछ इस तरह की बातें हो गयी हो तो वह बात अलग हो सकती है वरना बाढ़ के कारण हुए नुक्सान का मुआवजा देने का कार्य सुचारू रूप से हुआ है यह एक रिकार्ड की बात है। इस बारे में हमारे पास जो भी शिकायतें आती हैं उनको गर्वनमैंट के नार्म्ज के हिसाब से देखकर लोगों को राहत राशि दी जाती है और अगर फिर भी कोई शिकायत आती है तो अधिकारी मौके पर जाकर उन शिकायतों को देखते हैं। इस बारे में गवर्नमैंट के जो नोर्म्ज हैं, उनके अनुसार लोगों को राहत राशि देने की सरकार कोशिश करती है। मुख्यमंत्री जी भी सदन में बैठे हैं और मैं भी सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से भी हिदायतें मुआवजे की राशि देने के लिए हैं चाहे वे पशुओं के बारे में हों, आदमियों के बारे में हो या फिर ट्यूबवैल्ज के बारे में हो, जिस तरह का भी नुक्सान हुआ है उसका मुआवजा उनको हर हालत में दिया जाएगा। यह हो सकता है कि उस में समय थोड़ा ज्यादा बेशक लग जाए। इसके अलावा इन्होंने हिसार जिले के बारे में

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

भी कहा। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय साथी हिसार जिले के बारे में थोड़ी सी पौलिटीकल बात कर रहे हैं लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह इलाका तो इनके साथ लगता हुआ इलाका है। नारनौंद, बरवाला और नरवाना का जितना भी इलाका है उसके अंदर तो बहुत ही भयंकर बाढ़ आयी थी उस बाढ़ का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। (विघ्न) नारनौंद हल्का वह है जिसका एक भी गांव बाढ़ से नहीं बचा था इतनी भारी तबाही वहां पर हुई थी कि कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह कह कर कि हिसार जिला मुख्यमंत्री जी का जिला है इसलिए वहां पर ज्यादा मुआवजा दिया गया है, ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात करना बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही घिनौनी बात है इसलिए इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमें सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से जो ऐड मिली है, उसके बारे में मैं आपको फिगर्जवाईज बताना चाहूंगा। शोर्ट टर्म लोन और मिडियम टर्म लोन के रूप में हमें सरकार ने तीन सौ करोड़ रुपए दिए हैं। रिपेयर आफ ट्यूबवैल्ज के लिए चालीस करोड़ रुपए सैंट्रल गवर्नमैंट से मिले हैं। मिनिस्ट्री आफ रूरल एरियाज एंड ईम्पलायमैंट की तरफ से हमें 80 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। जे0 आर0 वाई0 और इंदिरा आवास योजना के तहत 15.54 करोड़ रुपये की सहायता हमें दी जा रही है। रूरल वाटर सप्लाई के लिए दस करोड़ रुपए और हुडको की तरफ से 36.55 करोड़ रुपए मिले हैं। फ्लड के दौरान जिस सैंट्रल टीम ने विजिट किया था और उनकी जो रिकमंडेशन आयी थी उसके अनुसार हमें एकदम से 39.41 करोड़ रुपये दिये गये। इसमें सैंट्रल गवर्नमैंट का जो शेयर है वह 17.74 करोड़ रुपये है। टोटल इससे 2.70 करोड़ रुपये बनते हैं और मिडियम टर्म लोन सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से हमें तीन सौ करोड़ रुपये दिया गया है जो कि हरियाणा के इतिहास में रिकार्ड की बात है। इतनी ज्यादा राहत प्राकृतिक प्रकोप के लिए सैंट्रल गवर्नमैंट की तरफ से पहले कभी नहीं मिली। इसके लिए हमें सैंट्रल गवर्नमैंट और मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही धन्यवादी होना चाहिए। इतने बड़े प्राकृतिक प्रकोप को जो कि केवल 36 घंटों में ही आ गया था सरकार ने केवल 15 दिनों में कंट्रोल किया और सारी राहत राशि स्टेट के हर वर्ग तक पहुंचाई। किसी भी मामले में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी गयी इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इनको इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : लोन पर क्या कोई इंट्रैस्ट भी देना होगा ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जितनी मदद हमारी की है, देश में कई जगह बाढ़ आई, तूफान आए और बहुत जगह जमीन भी हिली मगर हमें भारत सरकार से बड़ी भारी मदद मिली है। इसमें 300 करोड़ रुपया उन्होंने लोन की शक्ल में हमें दिया है और वह मुसीबत के समय में कोरी

तौर पर काम में लाने के लिए दिया है । हमने भारत सरकार से कहा है कि ब्याज माफ किया जाए और यह लोन जो दिया है उसके लिए भी हमने चिट्ठी लिखी है कि यह लम्बी अवधि 10 साल में वसूल किया जाए । ऐसा हमने भारत सरकार को लिखा है ।

डॉ॰ राम प्रकाश : इसका रेट ऑफ इन्ट्रैस्ट क्या है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, बैंकों का रेट ऑफ इन्ट्रैस्ट 18 से 20 परसैंट है इस लोन का उन्होंने 13 परसैंट रखा है फिर भी हम भारत सरकार को लिख रहे हैं कि लोन लम्बी अवधि का किया जाए और सूद माफ किया जाए ।

प्रो॰ राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सवाल के जवाब के "क" भाग में कहा है कि 1591 करोड़ रुपये की हानि हुई है । यह 1591 करोड़ रुपये की फसल की हानि कितने लाख एकड़ जमीन में हुई है जैसा पिछले सदन में बताया था कि लगभग 6 लाख एकड़ जमीन में पानी भर गया । यह पिछली फसल का अनुमान है क्योंकि दो फसलें उसमें बर्बाद हुई है आज भी लाखों एकड़ जमीन में पानी पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : यह रिप्लाई में दिया हुआ है ।

प्रो॰ राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं कैटेगरीकली जानना चाहता हूं कि यह एक फसल का अनुमान है या दो का है । मेरा दूसरा सवाल है कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आज तक इतनी मदद किसी प्रदेश की नहीं की जितनी हरियाणा प्रदेश की की है । जम्मू काश्मीर में प्राकृतिक आपदा न आने के बावजूद भी 80 हजार करोड़ रुपये की मदद जम्मू कश्मीर में दी गई है । ये 570 करोड़ रुपये को रिकार्ड कह रहे हैं यह बात सही नहीं है कि केन्द्र सरकार ने हमारी सबसे अधिक मदद की है यह कैटेगरीकली ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह क्वेश्चन नहीं है ।

प्रो॰ राम बिलास शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एक फसल का अनुमान है या आज भी जिन खेतों में पानी खड़ा है उसका अनुमान है ।

कृषि मंत्री (श्री हरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि हमारे साथी एक तरफ तो यह डिमांड करते है कि किसानों की मदद की जाए और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि ब्याज पर पैसा क्यों ले लिया । मैं कहता हूं चाहे इससे दुगुना ब्याज देना पड़े जिस किसान का नुक्सान हुआ है उसकी मदद होनी चाहिए ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : यह सरकार जवाब देने में आय बायें क्यों करती है ये बताते क्यों नहीं कि ये केस की पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर सके। (शोर एवं व्यवधान) ब्याज पर जो रकम मिली है उसको अनुदान कैसे कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी आनंद सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, अनैक्शचर-बी में जो सारी स्टेटमैंट दी गई है उसमें कम्पनसेशन की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो0 राम बिलास शर्मा : * * * * *

श्री अध्यक्ष : राम बिलास शर्मा जी जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाए। अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Incident of dacoity at Jhajjar

***1244. Chaudhri Om Parkash Beri** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any incident of dacoity and murder took place at Jhajjar on 17th January, 1996 ;

(b) whether any incident of firing/attempt to murder also took place at village Shekhupur Jat of district Rohtak on the same day i.e. 17th January, 1996, if so, the details thereof; and

(c) whether the culprits involved in the cases as referred to in part (a) & (b) above have been arrested ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी हां। दिनांक 10-1-96 को झज्जर में डकैती व हत्या की घटना हुई थी। इस सम्बन्ध में श्याम सुन्दर पुत्र नेम चन्द महाजन निवासी अनाज मण्डी, झज्जर के कथन पर मु0 नं0 18 दिनांक 17-1-96 धाराधीन 395/396 भा0 द0 स0 व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना झज्जर में अंकित हुआ। इस केस में 6 अज्ञात अपराधी एक मारुति कार में शिकायतकर्ता की दुकान पर आये और पिस्तौल की नोंक पर 30,000/- रुपये लूट लिए तथा एक ग्राहक लाला राम पुत्र गुलाब सिंह निवासी झज्जर जो वहां बैठा था, पर गोली चलाई, जिसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(ख) उसी दिन दिनांक 17-1-96 को गांव शेखपुर जाट में एक हत्या के प्रयत्न की घटना घटी। इस सम्बन्ध में महिन्द्र सिंह पुत्र उदय सिंह जाट निवासी शेखपुर के कथन पर मु0 नं0 21 दिनांक 19-1-96 धाराधीन 307 भा0 द0 स0 व 25/54/59 शस्त्र अधिनियम थाना झज्जर में दर्ज किया गया। उसने बतलाया कि दिनांक 17-1-96 को 5 अज्ञात अपराधी लगभग 8.30 बजे रात्रि एक मारूति कार में उसके घर आये और उनमें से एक ने मारने की नीयत से रिवाल्वर से उस पर गोली चलाई। गोली उसके शरीर के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ लगी।

(ग) जी हां। तीन अपराधियों को भाग (क) और दो अपराधियों को भाग (ख) में दिये गये मुकदमों में गिरफ्तार किया जा चुका है दोनों केसों में तीन-तीन अपराधियों की गिरफ्तारी बकाया है।

Mid-Day Meal Scheme

*1254. **Shri Ram Bhajan Aggarwal** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the details of the 'Mid-Day Meal Scheme' introduced in the Schools of the State; and

(b) the school-wise amount of expenditure incurred on the above said scheme during the period from 1st April, 1995 to todate ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) प्राथमिक शिक्षा के लिये पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य इन स्कूलों के बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाना, छात्र संख्या में बढ़ौतरी एवं उपस्थिति को सुनिश्चित करना तथा उनका पौष्टिक स्तर में सुधार करवाना है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1995 को रोहतक जिला के बल्लौर गांव से की गई। उसी दिन यह स्कीम हरियाणा के पांच अन्य जिलों—भिवानी, सिरसा, रिवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ के 19 स्कूलों में भी आरम्भ की गई। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिये सरकारी स्कूलों एवं सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों के प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिये (प्रति बच्चा प्रतिदिन 100 ग्राम की दर से) मुफ्त खाद्यान्न तथा उसका ढुलाई खर्च की सहायता दी जाती है। राज्य सरकार ने खाद्यान्न देने की बजाए अपने खर्च पर पका हुआ भोजन देने का निर्णय लिया। प्रारम्भ में राज्य सरकार ने इस स्कीम को सारे प्रान्त में लागू करने की घोषणा की थी परन्तु हरियाणा में अत्यधिक बाढ़ के कारण यह स्कीम भारत सरकार की स्कीम अनुसार 44 पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/रोजगार गारन्टी योजना खण्डों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों

[श्री फूल चन्द मुलाना]

में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्राथमिक श्रेणियों के बच्चों के लिये लागू की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत इन खण्डों में स्थित सहायता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों को भी सम्मिलित किया गया है। इन विद्यालयों की प्रबन्धक-समितियों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है और उन्हें कहा गया है कि वे बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाएं।

इस कार्यक्रम को भली प्रकार कार्यान्वित करने, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर समितियां गठित की गई हैं। पंचायतों, महिला मण्डलों, ड्वाकरा ग्रुपों आदि को खाना तैयार करवाने के लिये शामिल किया गया है।

(ख) विद्यालयवार सूचना एकत्रित नहीं की जा रही है। जितनी मेहनत विद्यालयवार खर्च एकत्र करने में लगनी है, उतने परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है। वैसे जिन जिलों में यह स्कीम लागू है उन्हें अब तक 11.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

Illegal possession of HUDA land in Faridabad

*1260. **Shri Azmat Khan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any case of illegal possession of the land of Haryana Urban Development Authority (HUDA) in Faridabad by some persons have come to the notice of the Government; if so, the details thereof, togetherwith the action taken to get the said land vacated therefrom ?

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल) : फरीदाबाद में हुड्डा की लगभग 80 एकड़ भूमि पर झुग्गी वालों का अवैध तौर पर नाजायज अतिक्रमण है। झुग्गी निवासियों को पुन: बसाने के माध्यम से इस नाजायज अधिक्रमण को हटाने के लिए वर्तमान एक योजना हुड्डा के विचाराधीन है।

Lala Jagat Narain and Ramesh Award

*1240. **Shri Kitab Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any IAS/IPS officers of the State Government have been awarded 'Lala Jagat Narain' and 'Ramesh Award' during the year 1995; if so, the details thereof; and

(b) whether the award as referred to in part (a) above may be given to the said officers under the law ?

मुख्य मंत्री : (चौ० भजन लाल) :

(क) जी, नहीं। वर्ष 1995 के दौरान हरियाणा के किसी भी आई.ए.एस. अथवा आई.पी.एस. अधिकारी को "लाला जगत नारायण" अथवा "रमेश अवार्ड" से सम्मानित नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Technology for effective control of Pollution

*1263. **Sathi Lehri Singh** : Will the Minister of State for Forests and Environment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to import technology/consultancy from other countries for the effective control of pollution in the State; if so, the details thereof ?

वन राज्य मंत्री (सत धर्मपाल) : श्रीमान, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Loan Granted by Haryana State Financial Corporation

278. **Shri Kitab Singh** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total amount of loan and subsidy given by the Haryana State Financial Corporation to each Industries in the State during the years, 1980-81 and 1981-82 togetherwith the names and addresses thereof ; and

(b) whether the recovery of the loan from the Industrialists as referred to in part (a) above has been made, if not, the reasons thereof togtherwith the action taken against them ?

Industries Minister (Shri A.C. Chaudhry) :

(a) The statements of loans sanctioned and subsidy given to the Industrial units in the State during the years 1980-81 and 1981-82 are given in @ Annexure I to IV.

(b) The list of cases, out of (a) above, where recovery is still pending are placed at@ Annexure V to VI. The loans in other cases have been recovered/adjusted.

@Kept in the Library

Sale of the land of Rehabilitation Department

279. Chaudhri Om Parkash Beri : Will the Minister for Rehabilitation and Consolidation be pleased to state—

(a) the names and addresses of the persons to whom the land of Rehabilitation Department has been sold/allotted in the State during the year 1995 todate togetherwith the rate at which it has been sold alongwith the location thereof ; and

(b) whether any complaint has been received by the Government form the Deputy Commissioner of Ambala, Yamunanagar, Faridabad and Panchkula districts in regard to the irregularities in the allotment of the above said land; if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon ?

राज्य मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा पते जिन्हें राज्य में वर्ष 1995 से अब तक पुनर्वास विभाग की जितनी भूमि बेची गई/अलाट की गई तथा इसे जिस दर पर बेचा गया तथा जहां पर भूमि स्थित है, का विवरण *अनुबन्ध "क" तथा "ख" में सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) उपायुक्त अम्बाला, यमुनानगर, फरीदाबाद और पंचकूला से कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । किन्तु अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला के उपायुक्तों द्वारा भूमि की बिक्री/अलाटमैंट के कुछ केसों की जांच की गई है तथा उनकी रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन है ।

Appointment of M.A./B.A.,B.Ed. Teachers on the posts of J.B.T.

280. Prof. Chhattar Singh Chauhan : Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the persons possessing the qualifications of M.A.,B.Ed. and B.A., BEd. have been appointed against the posts of J.B.T. teachers during the year 1995; if so, the reasons thereof, togetherwith the names & addresses of such appointees ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Yes Sir. On the recommendations of the Haryana Subordinate Services Selection Board, candidates having the higher qualifications of B.A. B.Ed etc. have been appointed as J.B.T. teachers during the year 1995, in terms of rule 7 of the Haryana Primary Education (Group C) District Cadre Service Rules, 1994.

So far as the names and addresses of such appointees are concerned, the time and labour involved in collecting this information will not be commensurate with the results expected to be arrived at.

---

*Kept in the Library.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेज दिए थे। हरियाणा के शिक्षकों में हरियाणा सरकार के प्रति बड़ा रोष है। पिछले कई दिनों से दो शिक्षक दिल्ली में हड़ताल पर बैठे हैं। हरियाणा सरकार का रवैया शिक्षकों की मांगों के प्रति ठीक नहीं है। वे चट्टोपाध्याय रिपोर्ट लागू करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसमें अकेले शिक्षकों का सवाल नहीं है बल्कि इसमें हरियाणा के लाखों छात्रों का भी सवाल है।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अध्यापकों की स्ट्राइक के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : पहले दलाल साहब अपने प्रस्तावों के बारे में कह लें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : दूसरा मेरा प्रस्ताव यह था कि हमारे तमाम हरियाणा के अन्दर पीछे बाढ़ आई थी जिससे किसानों और दुकानदारों वगैरह का बहुत नुक्सान हुआ था। इस पर पीछे सदन में चर्चा भी हो चुकी है लेकिन फरीदाबाद और मेवात में जो बाढ़ आई थी उसका मुआवजा अभी तक लोगों को नहीं दिया गया। वहां पर बहुत सारे मकानों को नुक्सान पहुंचा था। इसके अलावा आज भी किसानों के खेतों में पानी खड़ा है। तीसरा मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह था कि पलवल में जो शूगर मिल है वह उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ना खरीदता है और हमारे फरीदाबाद जिले के किसानों को पर्चियां नहीं दी जाती हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां के किसानों का ईख उनके खेतों में सूख रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि सरकार वहां के शूगर मिल को आदेश क्यों नहीं देती कि हरियाणा के किसानों का गन्ना पहले लिया जाना चाहिए। चौथा मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह था कि फरीदाबाद में बिजली की बहुत भारी कमी है जिस वजह से किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। अगर हरियाणा में किसी जिले में सब से ज्यादा बिजली कम दी जा रही है तो वह फरीदाबाद जिला है। उद्योगों को तो 24 घंटे बिजली मिलती है लेकिन किसानों को नहीं दी जाती। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैंने एक काम रोको प्रस्ताव हवाला कांड के बारे में दिया था। आपको पता है कि हर दिन चर्चा होती है कि हरियाणा के मुख्य मन्त्री इसमें शामिल हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता आज यह महसूस करती है कि अगर हरियाणा का मुख्य मन्त्री हवाला जैसे कांड में शामिल हो...........

श्री अध्यक्ष : क्या आपका कोई काल अटैंशन मोशन और है। अगर है, तो आप उस बारे में बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां आज हवाला कांड पर सारे देश में चर्चा हो रही है आप इस पर चर्चा करने के लिए कुछ घंटे फिक्स कर दें और उसके बाद मुख्य मन्त्री जी जवाब दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगर आपका कोई काल अटैन्शन मोशन और है तो बोलें वरना बैठिए ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : हमारे जिला फरीदाबाद में रोझों ने बहुत तबाही मचा रखी है । वे आए दिन फसलों को तबाह कर देते हैं । सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है । एक मेरा महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और है कि सारे हरियाणा में अपराध की गतिविधियां बढ़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष : रोझों के बारे में तो आपने कोई काल अटैन्शन मोशन नहीं दिया है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, वह आपको मिल जाएगा ।

Mr. Speaker : Dalal Sahab, we have not received as yet.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, एक काल अटैन्शन मोशन मैंने आपराधिक घटनाओं के बारे में दिया है । हर जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं । लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है । मेरे पलवल शहर में आज से 20 दिन पहले एक बच्चे को दिन दिहाड़े उठा लिया गया । इतने दिन के बाद भी हरियाणा पुलिस उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता सकी है । उस बच्चे के घर हर रोज टैलीफोन आते हैं कि अगर आप इस बच्चे की जान बचाना चाहते हैं तो फलां जगह 30 लाख रुपये भेज दो ।

सिंचाई मंत्री (श्री जगदीश नेहरा) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य अपनी काल अटैन्शन मोशन के बारे में उसका रैफ्रैंस दे कर ही फैक्ट पूछ सकते हैं । इस तरह से इनको लैक्चर नहीं देना चाहिए ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने 24 तारीख को दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपकी सेवा में दिए थे । एक ध्यानाकर्षण तो यह है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा प्रदेश में जो 1700 पुलिस कर्मी भर्ती किए गए थे उनकी भर्ती को रद्द कर दिया । पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रशासन द्वारा भर्ती करने के बारे में एतराज किया है और यह बात कही है कि भर्ती करने का कोई सिस्टम होना चाहिए । यह सरकार के ऊपर स्ट्रिक्चर है । दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजकीय स्कूलों के अध्यापकों द्वारा चलाए जा रहे आन्दोलन के बारे में दिया है । अध्यापकों ने यह बात कही है कि मार्च में होने वाले शिक्षा बोर्ड के इम्तिहानों में

वह डियूटी नहीं देंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन अध्यापकों की क्या मांगे हैं और उन मांगों को मानने में सरकार को क्या दिक्कत है । उनकी मांगों के बारे में सरकार उनके साथ बातचीत करके मामला सुलझा सकती है । अध्यापक दिल्ली में जन्तर-मन्तर मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं । तीसरा मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डबवाली अग्नि कांड के बारे में है । मैंने उसमें पूछा है कि सरकार ने उस कांड में मरने वाले लोगों के वारिसों को कितनी सहायता राशि दी है । ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों उसके बारे में सरकार ने क्या कारगर कदम उठाए हैं । मैं इन तीनों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के फेट जानना चाहता हूं ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, मैंने अध्यापकों के आन्दोलन के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है । जो अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है । वो जीवन संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है । चौधरी भजन लाल जी कहते हैं कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को फलां फलां रीलीफ दी है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार उन अध्यापकों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं और सरकार चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट लागू करना चाहती है या नहीं ?

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है । उसके बारे में शायद मुख्य मंत्री जी और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को पता नहीं होगा । भिवानी जिले के 6 गांवों में 25 तारीख को रात के 9.00 बजे 100 ग्राम से ले कर 200 ग्राम तक के ओले पड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने आज सुबह 9.40 बजे दिया है ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, उन गांवों में ओले पड़े हैं । मैंने इस बारे में भिवानी के डी० सी० से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनको इस बारे में पता ही नहीं है । वह गांव है बौंद कलां, बौंद खुर्द, रणकोली, राणीला इन गांवों की सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं । दूसरा मेरा काल अटैन्शन मोशन बिजली की कमी के बारे में है । आज भिवानी जिले में बिजली नहीं आ रही जबकि बिजली मंत्री कह रहे हैं कि 8–8 घण्टे बिजली दी जा रही है । आजकल बच्चों के पेपरों के दिन चल रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि ये 8–8 घण्टे तो क्या 6–6 घण्टे बिजली भी मुहैया करा दें तो इनकी मेहरबानी होगी ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भिवानी जिले में बाढ़ के कारण काफी सड़कें खराब हो गई थीं जिनको आज तक ठीक नहीं किया गया और एप्रोच रोडज को तो टच ही नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : रोडज़ के बारे में तो आपका कोई काल अटैन्शन मोशन नहीं है। आप बैठिये।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से दो मिनट में भी बोलना चाहता हूं। यहां पर बोलते हुए कुछ साथियों ने हवाला कांड का जिकर किया। यहां पर इन्होंने बोलते हुए कहा कि भजन लाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जैन डायरी में जो बी0 एल0 है उसका मतलब भजन लाल है। बी0 एल0 से बहुत से नाम हो सकते हैं। मैं आप लोगों की तरह नहीं कहता कि बी0 एल0 का मतलब बंसी लाल है। (शोर एवं विघ्न) आप मेरी बात सुनें। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जैन यह कह दे कि जिन्दगी में कभी मैं भजन लाल से मिला हूं या कोई दमड़ी दी है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। ऐसी बेहूदी बातें करना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों की तरह ओच्छी बात नहीं कहता।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पसर्नल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहता हूं।

चौधरी भजन लाल : चौधरी साहब, मेरी बात तो खत्म हो जाने दो। अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप बाद में पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोल लेना। मैंने यह नहीं कहा कि बी0 एल0 का मतलब बंसीलाल है। आपके साथी कहते हैं मैं नहीं कहता कि बी0 एल0 का मतलब बंसी लाल है। दिल्ली में खुराना साहब ने इस्तीफा दे दिया। भजन लाल इस्तीफा दे ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैंने हवाला कांड में किसी से कोई पैसा नहीं लिया। बी0 जे0 पी0 के साथ आप लोगों की समझौते की बात चल रही है। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जैन से मैं कभी नहीं मिला। जिस समय की बात यानि 1989 से 1991 की बात हरियाणा निवास की कर रहे हैं उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा निवास में ठहरने की बात तो दूर रही मैं उस रोड से तीन साल से गुजरा ही नहीं। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है और सी0 बी0 आई0 जांच कर रही है इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पर कोई चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। बी0 एल0 से मेरा नाम निकलता नहीं है। हवाला से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है न ही मेरा

नाम उसमें है । जब तक मैं जीऊंगा उसमें मेरा नाम आएगा भी नहीं । (विघ्न)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब और डा० राम प्रकाश जी, जो कालिंग अटेन्शन मोशंज दी हुई हैं, मुझे पहले उसके बारे में बताने दीजिए ।

Chaudhri Om Parkash Beri : Speaker Sahib................

Mr. Speaker : Beri Ji, please sit down. Let me tell about the calling attention motions. (Noise & Interruptions).

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर श्री कर्ण सिंह दलाल ने हवाला काण्ड के बारे में जो आपको "काम रोको प्रस्ताव" दिया है उसमें केवल चौधरी भजन लाल जी का नाम ही नहीं है बल्कि विपक्ष की तीनों पार्टियों का नाम है । हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी उसमें टिप्पणी है । इसके बारे में मुख्य मन्त्री जी कहें कि यह मैटर सब-जूडिस है या सी० बी० आई० की इन्क्वायरी चल रही है, यह ठीक नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि यह सवाल हरियाणा से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि उन शासकों और प्रशासकों से जुड़ा हुआ है जो हवाला काण्ड में लिप्त हैं । कईयों के खिलाफ चार्जशीट्स फाईल हो गई हैं और कईयों के खिलाफ चार्जशीट अभी फाईल होने जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे भी सबूत हैं अगर मैं उनको हाउस में नहीं रखूंगा तो मैं हरियाणा की जनता के प्रति अपने फर्ज से कोताही करूंगा । हरियाणा की जनता इस बात को समझे कि राजनीति में इस किस्म का भ्रष्टाचार है, अगर इसको इस तरह सहारा मिलता रहा तो देश की राजनीति बिगड़ जाएगी । हरियाणा की राजनीति बिगड़ जाएगी । हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स, हरियाणा के वे अधिकारी पिछले 15 साल से जो प्रशासन चला रहे हैं, इसमें लिप्त हैं । पिछले 15 साल से चाहे देवी लाल और उनके परिवार के लोगों का राज रहा, चाहे आज के मुख्य मन्त्री हैं और चाहे आज से कुछ साल पहले बड़े पदों पर बैठे नौकरशाही के लोग हैं, इन सारी चीजों को जनता के सामने रखना है । स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप "काम रोको प्रस्ताव" स्वीकार करें तथा सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करवाएं नहीं तो हम समझेंगे कि हमने हरियाणा की जनता को तथ्यों से अवगत नहीं करवाया है जो कि इस विधान सभा का फर्ज है और कर्तव्य तथा ड्यूटी भी है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत जोर से बात कह दी। इनकी बात पर मुझे किसी की कही बात याद आ गई कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज ये जिस तिवारी कांग्रेस में शामिल हैं उसके नेता अर्जुन सिंह और तिवारी दोनों ही हवाला काण्ड में शामिल हैं। उस तिवारी कांग्रेस में शामिल हो कर इनका खुद का भविष्य भी खत्म हो गया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा चैलेंज है जितनी बड़ी बात मैंने कही है दूसरा कोई नहीं कह सकता। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ब्यूरोक्रेटस के बारे में कह दिया उसमें कोई भी ब्यूरोक्रेट्स शामिल नहीं है। जहां तक इन्होंने मेरा नाम ले दिया है तो जैन आपके चैम्बर में आकर कह दे कि वह जिन्दगी में कभी भी मुझे मिला है तो मैं रिजाईन कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष : यह मोशन डिस-अलाऊ हो गया है। आपके जो काल अटैन्शन मोशन आए हुए हैं उनका जवाब सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

वाक-आउट

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम इसके विरोध में वाक-आउट करते हैं।

(इस समय अन-अटैचड मैम्बर श्री बीरेन्द्र सिंह, श्री ओम प्रकाश बेरी, भारतीय जनता पार्टी के श्री राम बिलास शर्मा और हरियाणा विकास पार्टी के सभी उपस्थित सदस्यगण सदन से वाक-आउट कर गए। इस समय प्रो० छत्तर पाल सिंह सदन के वैल में आकर बोलते रहे तथा कुछ मिनटों के बाद वे भी सदन से बाहर चले गए)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now I give my decision about the Call attention motions. The first notice is from Dr. Ram Parkash, M.L.A. regarding Dabwali Fire Tragedy the same has been sent to Government for comments. The second is also from Dr. Ram Parkash M.L.A. regarding appointment of 1700 constables quashed by Punjab & Haryana High Court. It has also been sent to Government for comments. The third is from Dr. Ram Parkash, Shri Karan Singh Dalal, and Shri Om Parkash Beri, M.L.As. regarding agitation of Government School Teachers in Haryana State. It has been disallowed. The fourth is from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding compensation to the flood affected houses of

villages in Palwal constituency. It is under consideration. The fifth is also from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding illegal digging of mines in Faridabad district. It is also under consideration. The sixth is also from Shri Karan Singh Dalal, M.L.As. regarding Law and Order situation in Haryana State. It is also under consideration. The seventh is also from Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding shortage of electricity in villages of Faridabad district, the same is admitted for 28th February, 1996. The eighth is from Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.A. regarding damage of crops due to hailstorms in Dadri Sub Division, it is under consideration. The ninth is from Shri Karan Singh Dalal and Shri Chhattar Singh Chauhan, M.L.As. regarding flood of September, 1995 causing an immense loss to the property, life and crops in the State, It is under consideration. (Noise & interruptions).

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move that the provisions of Rules 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

for the year 1996-97 be suspended.

Irrigation Minister (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the provisions of Rules 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes.

for the year 1996-97 be suspended.

[Shri Jagdish Nehra]

Sir, I also beg to move—

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1996-97 keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the provisions of Rules 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the:—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

for the year 1996-97 be suspended

and

Also that this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1996-97, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of Rules 228, 230, 230-B and 260-A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the—

(i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimate;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes & Scheduled Tribes

for the year 1996-97 be suspended

and

Also that this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 1996-97 keeping in view

the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The motion was carried.

वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates for the year 1995-96.

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के अनुपूरक अनुमान सदन में प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Shri Suraj Mal, Chairman of Estimates Committee, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 1995-96.

Chairman, Estimates Committee (Shri Suraj Mal) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates for the year 1995-96.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will take place. Shri Rajinder Singh Bisla may move his motion.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Shri Rajinder Singh Bisla (Ballabgarh) : Sir, I beg to move—

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the address which he has been pleased to deliver to the House on the 26th February, 1996."

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1991 में आम चुनाव हुए। हमने इन चुनावों में शांति एवं बहुमुखी विकास का लोगों से वायदा किया था। इन चुनावों में हमारी पार्टी को भारी जनादेश प्राप्त हुआ लेकिन यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जब हमारी इस लोकप्रिय सरकार का गठन चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ था तो उस समय सारा प्रदेश किस प्रकार से जात पात बिरादरी एवं शहर देहात की बीमारियों में जकड़ा हुआ था, बंटा हुआ था बल्कि मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा उस समय पूर्ण रूप से विभाजित था। उन सब हालातों को देखते हुए हमारी इस लोकप्रिय सरकार ने किस प्रकार से इस प्रदेश में जहां पर शांति, अमन एवं विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, नये सिरे से अपने कार्यक्रम चालू किए। पिछली सरकार ने विकास के नाम पर इस प्रदेश में एक ईंट तक किसी शहर या देहात में नहीं लगायी थी लेकिन हमारी सरकार ने आते ही विकास के कार्य प्रारम्भ किए। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम यह आवश्यक भी था क्योंकि औद्योगिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक विकास तभी हो सकता है जब प्रदेश में समाज के अन्दर रूल आफ ला हो, पूर्ण शांति हो एवं अमन हो। समाज का जो गरीब एवं पिछड़ा हुआ वर्ग है वह यह महसूस करे कि सारे समाज में कानून की व्यवस्था है तथा कोई भी दुःख तकलीफ नहीं है। किसी भी तकलीफ में उसे यह विश्वास हो कि अगर वह किसी कार्यालय में या किसी नेता के पास अपना काम करवाने के लिए जाएगा तो उसकी बात वहां पर सुनी जाएगी।

11.00 बजे | अध्यक्ष महोदय, आप भली भांति जानते हैं कि पिछले पांच सालों में हमारे प्रदेश में इतना विकास हुआ है कि सारे देश में किसी भी प्रदेश में इतना बड़ा भारी विकास नहीं हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है अमन और शांति का जो संदेश फैला है, इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, केन्द्र के नेता और प्रधान मंत्री जी ने दूसरे प्रदेशों में बार-बार यह कहा है कि अगर सुचारू रूप से प्रजातांत्रिक मूल्यों को सामने रखकर कोई सरकार चल रही है तो वह हरियाणा प्रदेश के अन्दर चल रही है। इसलिए हमारी सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में भी बड़ा भारी विकास हुआ है। अक्तूबर, 1995 में हमारे प्रदेश में बाढ़ का बड़ा भारी प्रकोप हुआ। मैं समझता हूं कि इस सदी की यह भयंकर कलैमिटी थी। हमारे प्रदेश के लाखों लोगों के जनजीवन को इसने अस्त-व्यस्त किया। प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में 8–8 और 10–10 फुट पानी खड़ा रहा जिसने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया। लेकिन जिस हिम्मत, हौंसले व दूर-दृष्टि से हमारी सरकार और प्रशासन ने प्रभावित लोगों को राहत दी वह अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। मेरे अपने क्षेत्र में यमुना नदी के परली तरफ गांव पड़ते हैं। जब बाढ़ आई तो वहां किसी भी प्रकार से राहत नहीं जा सकती थी। उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हैलीकॉप्टर तक उपलब्ध करवा कर रोटी, कपड़ा और दवाइयां उपलब्ध करवाई।

यह भी अपने आप में एक मिसाल है । बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमन्त्री जी, मंत्रीगण और अधिकारीगण किश्तियों से, ट्रैक्टरों और जुगाड़ों से पहुंचे यह निश्चित रूप से एक प्रेरणादायी काम है ।

इसी प्रकार से 23 दिसम्बर, 1995 को डबवाली नगर में भीषण अग्निकांड से सैंकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं । इस प्रकार का अग्निकांड शायद ही देश में पहले कभी हुआ हो । इसमें छोटे-छोटे बच्चे, उनके अभिभावक और टीचर्ज इत्यादि वहां जलकर राख हो गए । इस अग्निकांड से राहत देने के लिए जिस तत्परता, पूर्ण निष्ठा और लग्न के साथ हमारे प्रशासन ने कार्य किया है, यह अपने आप में बड़ा सराहनीय है । अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कुछ महीनों के बाद होने हैं और हमने लोगों के बीच में जाना है । यह इतना भारी मतदान होगा उसके लिए प्रशासन का दायित्व बनता है कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को तैयार रखे । उसे चुनाव के लिए तत्पर रखना नितांत आवश्यक है । यह कांस्टीच्यूशनल डियूटी है और इस डियूटी को ईमानदारी के साथ निभाने के लिए अगर कोई सरकार तत्पर है या जिसने पूरी तैयारी की हुई है तो वह हमारी हरियाणा सरकार ने की हुई है । हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में चुनाव पूर्ण ईमानदारी, अमन और शांति के साथ होंगे । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन मुद्दों को आधार बनाया है उन पर उन्होंने चर्चा की है । हमारे प्रदेश में एक ग्रीन रैवोल्यूशन हुआ है । सारे देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है और हमारा हरियाणा प्रदेश उसमें नम्बर वन पर है । जब हरियाणा का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारे इस हिस्से में बहुत कम फसल होती थी क्योंकि पानी और बिजली का पर्याप्त इन्तजाम नहीं था । लेकिन हमारे प्रदेश के मेहनती किसानों ने रात दिन मेहनत करके ग्रीन रैवोल्यूशन लाया और प्रदेश का विकास किया । इसके लिए जहां हमारे समस्त प्रदेश के किसान भाई बधाई के पात्र हैं वहां हमारी सरकार भी बधाई की पात्र है क्योंकि इसकी पालिसी प्रो–किसान है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक आवाज उठी थी । अखबारों में भी और हमारे नेता गण मंचों पर भी व्यक्त किया करते थे कि केवल मात्र कुछ परिवार एग्रीकल्चर पर ही डिपैंड करेंगे । आप जानते हैं क्योंकि जहां आप बहुत बड़े एजूकेशनिस्ट हैं उसके साथ साथ आप बेसीकली किसान भी हैं । सारे देश में हमारे प्रदेश की सरकार को श्रेय जाता है कि इसने एग्रीकल्चर की डाइवर्सीफिकेशन की है । यह हमारी सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम है और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है । हमारे प्रशासन ने हार्टीकल्चर और फलोरीकल्चर विभागों को बहुत सशक्त बनाया है । हमारे देश की राजधानी दिल्ली का आधे से ज्यादा बार्डर हरियाणा से लगता है । आज इन्हीं अच्छी नीतियों के परिणामस्वरूप आधी से ज्यादा दिल्ली को फलोरीकल्चर, हार्टीकल्चर और एग्रीकल्चर का उत्पादन हम देते हैं । इससे निश्चित रूप से किसान

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। एक बहुत बड़ी और उपलब्धि है जिससे सारे राष्ट्र को गौरव प्रदान हुआ है, उसके लिए भी हमारी सरकार को श्रेय जाता है। सारी दुनिया में मशरूम की जो कंजम्पशन है इसको देखते हुए यह अन्दाजा लगता है कि इसको खाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसकी ग्रोथ में हरियाणा प्रदेश सारे देश में नम्बर वन पर है। आज हजारों टन खुम्भी का प्रदेश में उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। खुम्भी उत्पादन के लिए हमने बहुत अच्छी पालिसी बनाई है और एक बहुत अच्छा इनफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है। 15 हजार टन मशरूम डिब्बा बन्द तैयार करना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जानते हैं कि ये कुछ ऐसी नीतियां हैं जिन से सीधा किसान को लाभ होता है। सोनीपत हो, गुड़गांव हो या फरीदाबाद हो आप इन सभी एरियाज में देखेंगे कि लोगों ने छोटी छोटी यूनिट्स लगा कर किस प्रकार से खुम्भी का उत्पादन किया है। जो हमारे बे-रोजगार बच्चे हैं वे सीधे दिल्ली या जिला स्तर के शहरों में जा कर अपना उत्पादन खुद बेचते हैं। इस से उनका आर्थिक स्तर ऊपर उभर कर आया है। यह सरकार की बहुत अच्छी नीति है। सरकार किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत है। इस प्रदेश में गन्ने का उच्चतम रेट किसानों को मिल रहा है। हमारी सरकार ने 75 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट फिक्स किया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में गेहूं का उत्पादन भी बड़ा भारी होता है और चने का उत्पादन भी होता है। सरकार ने गेहूं का रेट 380 रुपए प्रति क्विंटल और चने का 700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करके यह दर्शाया है कि हमारी सरकार किसानों की और ग्रामीण लोगों की कितनी हितैषी है। इस तरह से सीधा हमारे ग्रामीण भाईयों का जो लिविंग स्टैण्डर्ड है वह निश्चित रूप से ऊपर उभर कर आया है। अध्यक्ष महोदय, सारे देश में हमारे हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड की बड़ी भारी ऐतिहासिक भूमिका है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं बहुत लम्बे समय से प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए हैं। आपने भी हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन के पद को सुशोभित किया है। भाई जय प्रकाश जी हंस रहे हैं और बड़े खुश हैं। इन्होंने भी उस पद को सुशोभित किया है। भाई शेर सिंह जी इस समय उसके चेयरमैन हैं। मैं यह बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि चाहे गांव है और चाहे शहर है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां पर हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड की विकास की गतिविधियां न पहुंची हों। सारे प्रदेश में मंडियों का जाल बिछाया गया है। आज किसानों को मंडियों में अपना उत्पादन बेचने के लिए चार या पांच किलोमीटर से ज्यादा दूर अपना ट्रैक्टर या गड्डा नहीं ले जाना पड़ता है। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश सारे देश में प्रथम श्रेणी का राज्य है जहां किसानों को इस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हैं। सोनीपत जिले के राई क्षेत्र में 550 एकड़ क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक सब्जी और

फल केन्द्र बनाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। इसके लिए हमारी सरकार और समस्त अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। उस प्रोजैक्ट पर काम चालू है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, वह सब्जी और फलों का एक आधुनिक सैन्टर होगा। उसको विदेशों के लोग देखने के लिए आ रहे हैं। उससे हमारे प्रदेश के लोगों को बड़ा भारी लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां हमारी सरकार ने किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए अनेकों योजनाएं कार्यान्वित की हैं वहां हमारे प्रदेश का जो व्यापारी है उनको भी बहुत सारी राहतें दी हैं। हमारी हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों को सहूलियतें देने के उद्देश्य से बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं। मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी नशाबंदी को हाई लाइट करके एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही शराब चालू की थी। सारा प्रदेश और देश जानता है कि हरियाणा में चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में शराब को ज्यादा से बढ़ावा दिया था। इन्होंने ही अपने समय में सारे प्रदेश के गांवों में शराब के ठेके खोले थे। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। रोहतक जिला शुरू से ड्राई डिस्ट्रिक्ट रहा लेकिन चौधरी बंसी लाल जी के समय में उस जिले में सबसे पहले शराब बिकनी शुरू हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि हमारी सरकार ने यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में एक भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा। हमारी सरकार की यह एक क्रान्तिकारी घोषणा है। यह अपने आप में एक बहुत भारी क्रान्ति है क्योंकि आप समझते हैं कि शराब अपने आप में एक लानत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब शराब की ज्यादा खपत होती है तो उससे न केवल समाज के जो पैसे वाले लोग हैं वे ही प्रभावित होते हैं बल्कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं। इस शराब ने गांव के मजदूरों और किसानों के परिवारों को प्रभावित किया है। एक रिक्शा चालक या मेहनत-मजदूरी करने वाला सारा दिन कमाई करता है और शाम को वह अपने खून पसीने की कमाई को शराब में लुटा देता है तो उसका सारा प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है जिस कारण वह अपने परिवार का पालन-पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अब हमारी सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। और हमारे कई सामाजिक संगठनों ने भी इसमें सहयोग दिया है। विशेषकर हमारा जो आर्य समाज का संगठन है और महिलाएं हैं उन्होंने इस शराब को रोकने में एक जनमत तैयार किया कि सारे प्रदेश में शराब की खपत को कम किया जाना चाहिए। इससे सारे प्रदेश के लोगों का हैल्थ स्टैण्डर्ड अच्छा होगा। लोगों के रहन सहन में भी सुधार होगा और आपसी भाईचारा और प्रेम प्यार भी होगा। इससे किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि आगे से देहात में शराब का कोई ठेका नहीं खुलेगा। मैं समझता हूं कि इस कार्य के लिए सरकार को जितनी बधाई दी जाए कम है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

निर्णय से प्रशासन को फाईनेंशियल कंस्ट्रेंट तो जरूर होगा लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे अधिकारी और प्रशासन को कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। हमारा नेतृत्व इस कमी को किसी न किसी रूप में पूरा करने की कोशिश करेगा ताकि जो डिवैल्पमेंट के काम हैं वे उससे प्रभावित न हो सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश में जहां खेती को महत्व दिया जाता है वहां पर साथ ही साथ पशुधन को भी पूरा महत्व दिया जाता है। यहां के किसानों का खेती के साथ साथ पशुधन एक मुख्य व्यवसाय है। हमारे प्रदेश का कोई भी किसान मजदूर नहीं होगा जिसके पास पशुधन न हो। इसलिए हमारी सरकार ने पशुधन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे कारगर कदम उठाये हैं। ऐसी नीतियां कार्यान्वित की हैं जिससे पशुधन रखने वाले लोगों को उन स्कीमों का फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने पशुओं के ईलाज के लिए अधिक से अधिक डिस्पेंसरीज खोली हैं और होस्पिटल खोले हैं। सरकार ने पशुधन के लिए एक नया इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिस कारण अब पशुधन रखने वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही। सरकार ने यह एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और इसके लिए जितनी प्रशंसा सरकार की की जाए वह कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारी सरकार ने एस0 वाई0 एल0 नहर का पानी लाने का जो अहम् मुद्दा है उस पर भी बहुत अहम् निर्णय लिया है। एस0 वाई0 एल0 का पानी हरियाणा के लिए आना यहां के लोगों के लिए एक तरह से जीवन मरण का सवाल बना हुआ है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया हुआ है कि इस पानी को लाकर ही रहेंगे। हमारी सरकार ने इस सैंसेटिव मुद्दे को बड़ी सूझ बूझ के साथ परसू किया है। इस काम के लिए मैं चौधरी भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी सूझ बूझ के साथ इस मामले को निपटाने का फैसला किया है। इन्होंने कई राजनीतिक मंचों से यह घोषणा की है कि इस नहर का निर्माण करके सारे हरियाणा प्रदेश को पानी दिलाएंगे। यह सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत भारी औद्योगिकरण हुआ है तथा कृषि के क्षेत्र के अन्दर भी बड़ी भारी उंचाइयों तक उपलब्धियों को छूआ है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, पानी, वस्त्र और हवा है लेकिन मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है उससे बिजली भी आज जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। अगर दो मिनट के लिए भी बिजली चली जाती है तो उससे न केवल बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियलिस्टस बल्कि उनके साथ साथ गरीब और छोटे हर वर्ग के लोग भी प्रभावित होते हैं। उद्योगपति और साथ ही साथ किसान का काम भी बिजली के बिना नहीं चल सकता है। किसान और मजदूर के लिए आज बिजली का बहुत अधिक महत्व है। हमारी सरकार ने बहुत सूझ बूझ के साथ नई स्कीमें कार्यान्वित की हैं। ये

नई स्कीम्ज बिजली के उत्पादन के लिए बनाई हैं उनके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमारे विपक्ष के साथी बिजली के बारे में शोर मचाते हैं और कहते हैं कि यह नहीं है वह नहीं है। वे कहते हैं कि राज्य में आज पर्याप्त बिजली नहीं है, यह सरकार किसानों को बिजली नहीं दे पाती, उद्योगपतियों को बिजली नहीं दे पाती। लेकिन यह सच्चाई है कि पिछली सरकार के समय में बिजली का जो उत्पादन होता था उससे कई गुणा अधिक उत्पादन आज हमारे प्रदेश में बिजली का हो रहा है। जहां उत्पादन बढ़ा है वहीं कन्जम्पशन भी पहले से बहुत अधिक बढ़ी है। आज प्रदेश में इतना शांति और अमन का माहौल बना हुआ है कि देश के अन्दर और देश के बाहर के उद्योगपति हरियाणा में नये उद्योग लगाने के लिए लालायित हैं। चाहे वह किसान है, चाहे वह उद्योगपति है, बिजली के बिना सभी प्रकार का काम रुकता है और बिजली के बिना कोई उद्योगपति उद्योग लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। बिजली की जरूरत को समझते हुए हमारी सरकार ने फरीदाबाद में गैस पर आधारित 400 मेगावाट का यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया है। इसी प्रकार से यमुनानगर में 700 मेगावाट की क्षमता का यूनिट स्थापित किया जाना है। इसी प्रकार छोटी छोटी हमारी परियोजनाएं हैं उन पर शीघ्र ही काम चालू होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी सरकार ने प्रदेश के लोगों की मुश्किल को देखते हुए उन्हें किस प्रकार से पूरी बिजली उपलब्ध करवाई जा सकती है, इस बारे काम शुरू कर दिया है और नई-नई योजनाओं को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि जब इन योजनाओं का काम पूरा हो जाएगा तो सारे प्रदेश में लोगों को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध होती रहेगी। इस प्रयास के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। इस बारे में हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने विभिन्न अवसरों पर राजनीतिक मंचों से भी घोषणाएं की हैं। इस से स्पष्ट है कि हमारी सरकार बिजली के उत्पादन को कितना सीरियसली ले रही है और बिजली के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इससे पहले किसी भी सरकार ने, किसी भी मुख्य मन्त्री ने इस मुद्दे को इतनी गम्भीरता से नहीं लिया जितना कि चौधरी भजन लाल जी की मौजूदा सरकार ने ले लिया है। इसके लिए नई-नई योजनाएं चालू की गई हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए लेटैस्ट टैक्नोलोजी स्टेट में लाने के लिए वे तथा हमारे अधिकारी बाहर भी गए। नई टैक्नोलोजी आने से तेल और डीजल से भी बिजली का उत्पादन हो सकेगा। बिजली की जैनरेशन बढ़ेगी और निश्चित् रूप से सारे हरियाणा के लोगों को चौबीसों घण्टे बिजली मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी न केवल हमारे प्रदेश में है बल्कि जब हम हरियाणा प्रदेश से बाहर जाते हैं तो वहां पर भी यह कमी पाई जाती है, यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। दूसरे प्रदेशों में तो 12-12 घंटे तक बिजली का कट रहता है। हमारे प्रदेश में बिजली की व्यवस्था सबसे अच्छी है। इसके लिए हमारी सरकार गम्भीर है और वचनबद्ध है। इसके लिए भी निश्चित रूप से हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

हमारे प्रदेश में जहां इतना कृषि उत्पादन बढ़ा है वहीं पर उद्योगों का भी विकास हुआ है। इससे जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व किस प्रकार से किया जा रहा है। आज हर हरियाणवी भाई-बहन का भला सोचा जा रहा है और किस प्रकार से उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए, यह भी सरकार सोचती है।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगिक विकास के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, 1992 में हमारी सरकार ने एक परिवार से एक को रोजगार देने की योजना शुरू की थी। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। इस योजना को हम और मजबूती से लागू करेंगे ताकि जो परिवार अभी भी नौकरी से वंचित रह गए हैं उनको भी रोजगार दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार की एक और बहुत भारी उपलब्धि है। हमारी जो अहीर, सैनी, लोधा, गुज्जर और माली पांच जातियां हैं, उनको भी पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया है। ये जो भाई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, इनको भी रिजर्व वर्ग में करके इनकी सहायता करनी चाही है और यह बहुत भारी उपलब्धि है। इसके अलावा वृद्ध अवस्था के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में जितने भी गरीब और अनपढ़ लोग हैं। वे अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं और हमारी सरकार ने हरियाणा के अन्दर हैल्थ के लिए जितनी अच्छी सर्विस प्रदान की है वह देश के अन्दर देखने को भी नहीं मिलती है। इस बारे में बहुत भारी सुधार की कोशिश की है। सारे प्रदेश में अस्पतालों का जो नेटवर्क है उसका आधुनिकीकरण करके बहुत ही अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बड़ी भारी उपलब्धि हमारी सरकार की है। हम सबने महसूस किया है कि 9 दिसम्बर, 1995 एवं 20 जनवरी, 1996 को पोलियो विरोधी अभियान पूरे देश में चलाया गया था उसके तहत तीन वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी गयी थी। हमारी सरकार ने इस प्रोग्राम को बहुत ही शानदार तरीके से चलाया। हमारी सरकार ने इस अभियान को गांव गांव तक गरीब से गरीब किसान के घर तक और मजदूर तक चलाया। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, डाक्टरों ने एवं अधिकारियों ने पूर्ण ईमानदारी के साथ इसमें भाग लिया और चलाया। सारे देश में हमारा प्रदेश पोलियो विरोधी अभियान में प्रथम रहा है। इसलिए यह एक बड़ी भारी उपलब्धि रही है। इसी तरह से हमारी मोबाइल डिसपैंसरीज की योजना भी बहुत लोकप्रिय रही है। मोबाइल डिसपैंसरीज लोगों को बहुत ही सुविधा उपलब्ध करवाती रही है लेकिन अभी इस योजना को और स्ट्रैंथन करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बड़ी उपलब्धि की

है। वैसे तो कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल न हो। लेकिन चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में शिक्षा विभाग पर जितना पैसा खर्च किया गया है, नये नये स्कूल खोले गए हैं और हमारी बहन बेटियों के लिए बी०ए० तक की शिक्षा के लिए जो फ्री व्यवस्था की गयी है उसके लिए भी सारे देश में हमारी सरकार की ऐजुकेशन की नीति की प्रशंसा की गयी है। इस सरकार ने सैंकड़ों स्कूल अपग्रेड किए हैं और महिलाओं की शिक्षा पर बहुत बल दिया है। इसलिए यह निश्चित रूप से सरकार की एक और बड़ी भारी उपलब्धि रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में वैसे तो सारे गांव मैटल-रोड से जुड़े हुए हैं लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने सड़कों का नवीनीकरण किया है और जो सड़कें छोटी थीं तथा जिन पर ट्रैफिक ज्यादा था उनको जिस तरह से अब चौड़ा किया जा रहा है वह बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक फोर लेनिंग की बात है, दिल्ली से लगते हुए जितने भी नेशनल हाईवे हैं या स्टेट हाईवे हैं, उन पर बहुत काम इस सरकार ने किया है। शायद ही इससे पहले इतना काम कभी हुआ हो। यह श्रेय हमारी इस सरकार को और मुख्यमंत्री जी की जो दूर दृष्टि एवं अनुभव है, को दर्शाता है। पिछली सरकार ने तो दिल्ली से करनाल तथा चण्डीगढ़ तक फोर लेनिंग करने की योजना लागू ही नहीं की। अगर वह सरकार चाहती तो यह योजना लागू हो सकती थी लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। परन्तु चौधरी भजन लाल जी ने जिस तरह से इसको टेकअप किया और 24 घंटे फोर लेनिंग का काम शुरू करवाया, वह बड़ी भारी उपलब्धि है। इसी तरह से इस सरकार की एक और बड़ी भारी उपलब्धि रही है। दिल्ली से मथुरा-आगरा के लिए जो नेशनल हाईवे है वह सारे वर्ल्ड की और विशेषकर एशिया की सबसे अच्छी कंक्रीट की बनी हुई सड़क है। यह सड़क हमारे फरीदाबाद और पलवल से होती हुई जाती है। यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम थी लेकिन इस स्कीम को केवल हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही टेकअप किया। टाईटलर साहब जो कि केन्द्र में उस समय मंत्री थे, उनको लेकर उन्होंने बड़ा भारी फंक्शन वहां पर किया और इस करोड़ों रुपये की योजना को चालू करवाया। आज यह बहुत ही अच्छी सड़क बनायी जा रही है। यह एशिया की सबसे अच्छी सड़क है, यह भी सरकार की एक बड़ी भारी उपलब्धि है। आज कई और गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जा रहा है। हमारे पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा एवं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कों को ठीक किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सारे प्रदेश में जो हमारी शुद्ध पेयजल की योजना है, वह हर गांव में पहले से उपलब्ध है। पानी की जो मात्रा है, क्वालिटी है या क्वांटिटी है, उसकी तरफ हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। हमारी सरकार चाहती है कि मनुष्य को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा व पानी की आवश्यकता है। पहले जहां लोगों को पीने का पानी कम मात्रा में उपलब्ध होता था, उसको बढ़ाया है। सरकार ने इन साढ़े चार सालों में पब्लिक हैल्थ का जो विभाग है इसको निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से चलाया है और सारे देश में हरियाणा पहला प्रदेश है जहां शुद्ध पेयजल की रिक्वायर्ड क्वान्टिटी है। वह हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है, यह भी हमारी उपलब्धि है।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

[श्री राजेन्द्र सिंह बिसला]

जहां छोटी-छोटी ढाणियां हैं वहां भी अनेक योजनाओं के द्वारा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज न केवल दूसरे देशों में बल्कि हमारे देश में भी पर्यावरण के बारे में एक जनजागरण आंदोलन चला हुआ है। चाहे सोशल रिफौर्मर हों, सामाजिक संगठन हों, इन लोगों ने किस प्रकार से आम आदमी के दिमाग में पर्यावरण की समस्या के बारे में जागृति क्रिएट की है। आज साधारण से साधारण आदमी भी समझता है कि किस प्रकार धुएं से, गंध से और शुद्ध हवा पानी न मिलने से आदमी बीमार होता है। उसके लिए चालू वित्त वर्ष में हमारी सरकार ने कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में सांझा जल संशोधन संयंत्र चालू किया है और वर्ष 1996-97 में जींद, समालखा व अम्बाला में ऐसी परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी जो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सबसे आगे बढ़कर हमारी सरकार ने फरीदाबाद में एक विशेष पर्यावरण अदालत की स्थापना की है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जहां कानून व्यवस्था का, सिस्टम का और रूल्ज का वायलेशन होता है तो उसमें दंड देने की भी क्षमता होनी चाहिए। उस सिस्टम में ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए। अब लोगों में यह जागृति आई है और वे यह ड्यूटी भी मानते हैं कि अगर हम पर्यावरण को खराब करेंगे, ज्यादा धुंआं छोड़ने वाली कार इस्तेमाल करेंगे, बस इस्तेमाल करेंगे या फैक्ट्री चलाएंगे तो पर्यावरण की अदालत के माध्यम से हमें सजा भी मिलेगी। मैं समझता हूं कि पर्यावरण शिक्षा और जागृति के लिए यह एक बड़ी भारी उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि से, एरिया के हिसाब से या पापुलेशन के हिसाब से हरियाणा प्रदेश सारे देश में छोटा प्रदेश माना जाता है। लेकिन जहां हमारे प्रदेश की अनेक महान उपलब्धियां हैं वहां खेलकूद में भी हमारे यहां के खिलाड़ियों ने हमारे राष्ट्र को बड़ा भारी गौरव प्रदान किया है। क्रिकेट, कबड्डी या रैसलिंग हो, यह समस्त लोगों के लिए फख्र की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी रैसलर हुए हैं, रुस्तमे हिन्द हुए हैं या भारत केसरी हुए हैं और भी हुए हैं इनमें से 90 फीसदी हरियाणा प्रदेश से हुए हैं। यह भी एक बड़ी भारी उपलब्धि है। हमारी सरकार का ज्यादा से ज्यादा नौजवान युवकों को खेल के माध्यम से बढ़ौतरी देने का प्रयास है। इस प्रकार से सरकार ने जो कार्यक्रम चालू किए हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं कहना चाहता हूं कि एक बार फिर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अपना रोल अदा करेंगे। हमारी सरकार अपने कर्मचारियों के बारे में भी जागरूक है कि उनको किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। हमारी सरकार इसके लिये कार्यरत है। इन शब्दों के साथ मैं सदन के सभी माननीय साथियों से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

साथी लहरी सिंह (रादौर, अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज यह प्रस्ताव जो श्री राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने रखा है कि महामहिम राज्यपाल

महोदय ने जो हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की है उसके लिए यह सदन उनका आभारी है, मैं इसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में महामहिम जी ने एक ऐसी कृपा की है कि उन्होंने सरकार की जो कार गुजारियां हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से ब्यान किया है। उन्होंने हरियाणा के निवासियों को संबोधित करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। सब से पहले मैं आज की सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं जैसे कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया कि नेता की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जो राजा है वह प्रजा के लिए जो स्कीम बनाता है उससे यह नजर आता है कि वह स्टेट को कैसे चलाना चाहता है। तो उसमें सब से बड़ी बात यह है कि हरियाणा के किसी भी कोने में जैसे हालात पहले थे उनको सुधार कर सरकार ने नियंत्रण में किया है। सब से बड़ी बात यह है कि हालात वहां खराब होते हैं, जैसे इन्सान यहां चण्डीगढ़ में बैठा हो और यहां से टैलीफोन कर दे कि फलां को अन्दर कर दो और फलां को बाहर कर दो। ऐसा कोई उदाहरण हमारी सरकार की ओर से या मुख्य मन्त्री की ओर से देखने को नहीं मिलेगा कि उन्होंने अफसरों को किसी प्रकार की गलत सिफारिश की हो। हम लोग भी अपनी अपनी जगहों पर रहते हैं लेकिन ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। यहां पर तो मैरिट और न्याय की बात होती है और वही लोगों को मिलती है। इससे बढ़ कर स्वच्छ प्रशासन आज तक कोई सरकार नहीं दे सकी। इसीलिए राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूं और आज की सरकार को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा था कि यह संसार है और इसमें दुख सुख आते जाते रहते हैं। एक कहावत मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार अकाल पड़ गया। उस समय एक घर में आटा नहीं था। उस घर की बुढ़िया किसी से आटा मांग कर लाई और रोटी बनाने लग गई। उस घर में चार आदमी थे लेकिन उस आटे की रोटियां बनी तीन। जैसे ही रोटी पकी तो उसने एक रोटी अपने पैर के नीचे रख ली। उसने सोचा कि एक रोटी मैं अपने लिए रख लेती हूं और बाकी की दो को तीन आदमी खा लेंगे। ऐसा करते हुए उस मां का बच्चा देख रहा था। उस बच्चे ने यह कहा कि मां यह जो अकाल पड़ा है यह तो चला जाएगा लेकिन तूने अपने पैर के नीचे जो जलती हुई रोटी छिपाई है इसका दाग सारी जिन्दगी नहीं जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस स्टेट के अन्दर बाढ़ का प्रकोप आया तो उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री ने, हरियाणा सरकार ने यह कोशिश की कि हर आदमी की जान बचाई जाए, उसकी फसल भी बचाई जाए और जो नुकसान हुआ है उसका जायज मुआवजा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ के समय हमारी सरकार ने किसानों की जो मदद की उसकी मिसाल कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हमारे प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार भी रही लेकिन उन्होंने भी इस तरह से लोगों की मदद नहीं की। उस दौरान हमारी सरकार ने लोगों की जो मदद की उसकी मिसाल सारे भारत वर्ष में नहीं मिलेगी। इस बात का जिक्र हमारे राज्यपाल महोदय ने भी

[साथी लहरी सिंह]
अपने ऐड्रैस में किया है । मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि अगर नेता की नीयत अच्छी होगी तो प्रशासन भी बहुत अच्छा चलेगा । अगर नेता की नीयत खराब होगी तो प्रशासन में भी गड़बड़ हो जाएगी । लेकिन हमारे नेता की नीयत अच्छी है इन्होंने इस बात का सबूत दिया है । हमारे डी0 सीज0, एस0 पीज0 और दूसरे औफिसर्ज ने दिन रात मेहनत करके उस समय लोगों की सहायता की । डी0 सी0 यमुनानगर ने रात के 12.00 बजे जा करके, जिन गरीब आदमियों के घर गिर गए थे जिनके घरों में मौतें हो गई थी, उनको सान्त्वना दी । मैंने कुरूक्षेत्र, अम्बाला जिला यानि तीन चार जिलों को पर्सनली देखा उन जिलों के लोगों को सभी सहुलियतें पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मेहनत की । जो औफिसर्ज अपने घरों में एयर कंडीशंड कमरों में बैठते थे उन सभी सुख सुविधाओं को छोड़ कर वे औफिसर्ज बाकायदा बाढ़ से पीड़ित लोगों के पास गए और उनको सहुलियतें दी । उन्होंने बाकायदा एक नेक इन्सान की तरह से लोगों की मदद की । इसके लिए मैं उनको दाद देना चाहता हूं । हमारे पशु पालन मंत्री जी सदन में बैठे हैं । इनके विभाग के एक चिकित्सक ने डंगरों के साथ डंगर बन कर काम किया जो बेजुबान प्राणी हैं उनकी भावना को उन्होंने समझा ।

सिंचाई मन्त्री (श्री जगदीश नेहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इन्सान को डंगर के साथ मिलाया है । इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए । यह अच्छा नहीं लगता ।

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा है कि उन चिकित्सकों ने डंगरों की बेजुबान भाषा को समझ कर उनका ईलाज किया । इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहन करतार देवी जी को भी मुबारिकबाद देना चाहूंगा । इनके महकमे के एक एक चिकित्सक ने हर जगह जा कर लोगों की मदद की । यह पहला चांस है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर इतनी भयंकर बाढ़ आई । उपाध्यक्ष महोदय, संवत 81 की बात है उस समय बाढ़ की वजह से एक ऐसी बीमारी फैली जिससे लोगों की जान बचानी मुश्किल हो गई थी । उस बाढ़ के कारण एक एक घर से 10-10 अर्थियां निकली थी । मैं बहन करतार देवी और चौधरी भजन लाल जी को मुबारिकबाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा इन्तजाम करके बाढ़ के दौरान कोई बीमारी नही फैलने दी । हमारे इलाके में बाढ़ का 10 से लेकर 12 फुट तक पानी आया और उसको कंट्रोल किया । यह इनकी अच्छी नीयत का ही फल है । मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर नेता की नीयत अच्छी होगी तो प्रशासन भी अच्छा काम करेगा । उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी नीयत साफ होती है उसका सभी साथ देते हैं । हमारे यहां पर जब बिजली की दिक्कत आई तो भगवान की कृपा से समय पर बारिश हुई । आज हरियाणा में फसल बहुत बढ़िया है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर । बार बार ये एक बात कहे जा रहे हैं कि जिसकी जैसी नीयत होती है वैसा ही काम होता है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनकी नीयत ऐसी थी कि यहां पर बाढ़ आये और लोगों का नुकसान हो । क्या इनकी नीयत यही थी कि यहां पर 10–10 फुट पानी खड़ा रहे । ये अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये किस नीयत का हवाला यहां पर देना चाह रहे हैं । क्या इनकी नीयत यही थी कि यहां पर तबाही मचे ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है ।

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुसीबतों से निपटने के लिए जिसकी जैसी नीयत होती है उसका उसी हिसाब से काम होता है । हमारे नेता की नीयत अच्छी थी तभी तो सारे काम ठीक हुए । यहां पर बहुत अच्छी फसल खड़ी है । यहां पर जितनी मुसीबतें आईं उन मुसीबतों को लोगों ने और सरकार ने कंधे से कंधा मिला कर दूर किया । हमारा हरियाणा प्रदेश पहले 10वें 11वें नम्बर पर था आज वह बहुत अच्छी स्थिति में है । हमारा कुरुक्षेत्र जिला पैदावार के मामले में सारे देश में प्रथम आया है । (विघ्न) यह इसलिए संभव हो पाया कि सरकार ने समय पर किसानों को बीज मुहैया करवाया, खाद मुहैया करवाया और समय पर दवाइयों आदि का समुचित प्रबंध किया । आज हमारा प्रदेश पैदावार में नम्बर वन पर है । आप यहां की किसी भी फसल को ले लें, चाहे वह गन्ने की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है या धान की फसल है सबके भाव बड़े अच्छे हैं और सारी फसलें पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो रही हैं । आज सारे देश के लोग कहते हैं कि हमें चाहे मोटा चावल ही दे दो लेकिन वो हो हरियाणा का । आज किसान की हालत पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सुधर गयी है । जहां जीरी 700 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी वह 1000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है । जिस जीरी का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल था वह 800 रुपये में बिक रही है । यह सब किसानों की सूझबूझ और सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के कारण ही संभव हो पाया है । मैं पुनः सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने हर दिशा में सही पग उठाये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह बिजली मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके बिजली की कमी को दूर करने के लिए पग उठाये । इनकी इस बात के लिए भी सराहना करता हूं कि जब बिजली का संकट आया और बिजली की कमी हुई तो इन्होंने सरेआम इस बात को स्वीकार किया कि अब बिजली की कमी है । इन्होंने यह बात हाउस में खड़े होकर और पब्लिक मीटिंगों में भी स्वीकार की । इनकी सूझबूझ और हमारे मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी के आदेशों पर इन्होंने दिन रात मेहनत करके बिजली की कमी को पूरा किया । इन्होंने बिजली का ऐसा इंतजाम किया कि लोगों को बिजली की कमी

[साथी लहरी सिंह]

महसूस नहीं हुई । जब बिजली की आवश्यकता अधिक पड़ी तो भगवान की कृपा दृष्टि से समय पर बारिश हुई जिसके कारण आज सारे प्रदेश में सारी फसलें बहुत अच्छी लहलहा रही हैं । हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का मुकाबला कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, 23 तारीख की रात को जब टी0 वी0 पर मैंने डबवाली अग्निकांड को देखा तो उस समय मैं खाना खा रहा था तो उसी समय मैंने खाना छोड़ दिया (विघ्न) कोई भी इन्सान इस प्रकार की हृदय विदारक घटना को देख कर भावुक हो सकता है । उसको देख कर मेरे दिल पर एक चोट सी लगी । मैं रात को वहां से चला और सवेरे डबवाली पहुंचा । मैंने उस हृदय विदारक दृश्य को देखा । वहां पर डेढ़ सौ बच्चों की ऐसी लाशें पड़ी हुई थी जिनको पहचाना ही नहीं जा सकता था । उन लाशों को देख कर मेरा दिल रो पड़ा । वहां पर उसी वक्त मेरी उम्र का एक आदमी आया उसने लाशों को देखा तथा रोते और बिलखते हुए एक बच्चे की लाश को उठाया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी आदरणीय हैल्थ मिनिस्टर महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हिसार, सिरसा, और रोहतक तक के डाक्टरों को एकदम वहां पर डयूटी पर भेज दिया । इतना अच्छा इन्तजाम कोई नहीं कर सकता जितना इन्होंने वहां पर किया । मैं इनको वास्तव में वीर बहन समझता हूं । इन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया । (विघ्न)

प्रो0 राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि चौधरी लहरी सिंह जी डबवाली काण्ड के बारे में चाहे कुछ भी कहें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें लेकिन अपनी बात को पोलिटिक्लाईज न करें । उन्हें जो दुख हुआ है उस बारे जो कुछ कहना है वह कहें । लेकिन वहां पर जब जीवित लोग और बच्चे जल रहे थे उस समय इनका डी0 सी0 कहां था । किस प्रकार वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था । कई पत्रकार और दूसरे लोग वहां पर लोगों को बचाने में लगे हुए थे लेकिन डी0 सी0 50 बच्चों को कुचलता हुआ अपनी जान बचा कर भाग निकला । आप इस बारे भी कुछ कहें । (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि जैसे साथी लहरी सिंह जी ने डबवाली अग्निकाण्ड का जिक्र किया और भावुक हो रहे हैं कि वहां पर बच्चे जल गए । ये केवल सहानुभूति बटोरने की बात न करें बल्कि यह भी बताएं कि उन बच्चों के वारिसों के लिए इन्होंने अपने हल्के से राहत पहुंचाने के लिए क्या किया और अपनी जेब से इन्होंने क्या दिया । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके हाउस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इनका पैट्रोल पम्प है, पैसा है, इन्होंने अपनी जेब से या हल्के से वहां कितनी राहत पहुंचाई है ।

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं थी। डबवाली में जो आग लगी उससे सभी का दिल दहल गया था। मैं रादौर के लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने डबवाली काण्ड के लिए काफी मदद दी। इस समय इसका विवरण मेरे पास नहीं है लेकिन विवरण इकट्ठा करके मैं हाउस में बता दूंगा। सहायता किसी भी प्रकार की दी जा सकती है जैसे कपड़ा, अनाज या नकद पैसा जितनी मदद हो सकती थी वह रादौर के लोगों ने की है और मैंने भी की है। (विघ्न)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, ये कोरी सहानुभूति प्रकट करने की बात कर रहे हैं, ये बताएं कि इन्होंने अपनी पर्सनल पॉकेट से क्या दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको बार बार न टोकें। इनको बोलने दें।

साथी लहरी सिंह : मैंने भी एक महीने की तनख्वाह दी है। (विघ्न एवं शोर) रादौर से भी सहायता वहां पर भेजी है और मैंने खुद भी सहायता दी है। है। (विघ्न एवं शोर) मेरी उम्र का एक आदमी वहां पर आया और उसने सभी बच्चों की लाशों को देखा। (विघ्न एवं शोर) उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाउस चल

12.00 बजे | रहा है और जितना अमाउन्ट रादौर से गया है और जितनी तनख्वाह मेरी है वह आपको पता करके मैं कल बता दूंगा। (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक आदमी वहां आया और उसने कहा कि मुझे पता नहीं है कि इनमें से मेरे बेटे की लाश कौन सी है। लेकिन मैं इस बच्चे की लाश को ले जाकर इसका संस्कार कर दूंगा ताकि मेरे मन को शान्ति मिले कि मैंने अपने बेटे का अन्तिम संस्कार कर दिया है। वहां पर इस प्रकार के हालात थे और ये यहां पर हंस रहे हैं। (विघ्न) मैं यह कह रहा हूं कि वहां पर बहुत बड़ा अग्नि कांड हुआ और सरकार ने वहां पर राहत पहुंचा कर बहुत ही अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब हम शादियों में जाते हैं तो वहां पर टैंट वाले आग बुझाने के लिए सामान रखते हैं। यह जो घटना हुई थी वह भारतवर्ष में पहली घटना थी। मैं यह कहता हूं कि सरकार अब ऐसा कार्य करे ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा से न हो पाए।

इसी तरह से कृषि के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों की स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने जो पग उठाया है, राई में सब्जी मंडी और फल मंडी बनाई गई है यह बहुत ही अच्छा काम है। जब राई सब्जी मंडी इन्टरनैशनल मार्किट बन जाएगी तो बाहर की ताजी सब्जियां यहां आएंगी और यहां की ताजी सब्जियां बाहर जाएंगी जिससे बहुत ही फायदा होगा। वहां पर आज जो किसान 10 हजार रुपया कमाता है उस मंडी के बन जाने के बाद वह 1 लाख रुपया कमाएगा। इससे वहां के किसानों के, मजदूरों के हालात सुधरेंगे। ये सब बातें इस बात का सबूत हैं कि यह सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि प्रदेश के हर वर्ग को ऊपर उठाया जाए और ये भारत सरकार को भी कह सकें कि हमारा

[साथी लहरी सिंह]

हरियाणा-वासी किसी तरह से तंग नहीं है। इसमें आप सब भाईयों को भी मदद करनी चाहिए। आज तक अगर आपने कोई अच्छी बात कही है तो सरकार ने उसको माना भी है। यह जो मण्डियों का काम चल रहा है इसके लिये मैं शेर सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ भी बहुत अच्छा काम किया गया है जो हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का काम हो जाएगा। आज आप कालका से लेकर राजौंद तक चले जाएं, और उधर डबवाली से लेकर यमुना-नगर तक आप चले जाएं आपको हर हल्के में सड़कों का कोई न कोई काम होता हुआ जरूर मिलेगा। आप सभी लोग यहां पर बैठे हैं इसलिये आपको पता है कि सरकार ने हर एम० एल०ए० को उनकी अपनी कांस्टीच्यूएंसी के विकास के लिये चालीस लाख रुपये या पचास लाख रुपये दिए हैं। दलाल साहब को भी अपने हल्के के विकास के लिये यह राशि दी गई है लेकिन इन्होंने अपने हल्के में विकास का काम करवाया है या नहीं यह तो ये ही जाने लेकिन सरकार ने निष्पक्ष तरीके से हर हल्के में विकास के काम करवाने की कोशिश की है। ये बता दें कि सरकार ने विकास के काम करवाए या नहीं करवाए इससे ज्यादा निष्पक्ष बात और क्या हो सकती है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

साथी लहरी सिंह : सर, मैंने इसमें कौन सी बात कह दी जो ये प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : सर, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हर एम०एल०ए० को अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसी के विकास के लिये पचास लाख रुपये दिये गये हैं मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसा केवल कागजों में ही दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य-मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना कितना पैसा आज तक दिया गया है? मैं भी एम०एल०ए० हूं मेरी कांस्टीच्यूएंसी में 1994-95 का पैसा नहीं गया है। 1995 में केवल सैकेंड और थर्ड फेज की चिट्ठी गई है इसलिये मैं इनसे कहूंगा कि ये इस तरह की बात कहकर सदन को गुमराह न करें। ये स्वयं ही बता दें कि इनकी कांस्टीच्यूएंसी में कितना-कितना पैसा लगा है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में तो आज तक दस लाख रुपये से ज्यादा नहीं लगा है। (विघ्न) मैं चेयर को ही ऐड्रैस कर रहा हूं। Sir, who is he to interrupt me like this?

Mr. Deputy Speaker : Is this the occasion to ask this question?

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : सर, मैं आपसे एक रूलिंग चाहता हूं। मैं तो आपकी इजाजत से ही खड़ा होकर बोल रहा हूं फिर ये मुझे बीच में क्यों टोक रहे हैं। (विघ्न) मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी कोई अपोजीशन का आदमी बोले तो इनको उसको सुनना

चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो लहरी सिंह कह रहे हैं कि हर एम०एल०ए० को 50 लाख रुपये दिये गये हैं, this is far from the truth and facts. (Noise & Interruptions).

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, छतर सिंह चौहान वैसे तो बुजुर्ग आदमी हैं इसलिये इनको क्या कहें। हम तो समझते थे कि ये हाउस में तो कम से कम सच बोलेंगे। यह स्वयं बता दें कि क्या यह बिल्कुल झूठी बात है कि इनके यहां एक भी पैसा नहीं दिया गया है। हमने चालीस लाख रुपये एक बार दिए और दस लाख रुपये फिर बाद में भेज दिए। टोटल पचास लाख रुपये हर एम०एल०ए० को चाहे वह रूलिंग साईड का हो या अपोजीशन साईड का हो, सबको दिये गए हैं। अगर ये अपने हल्के में जाकर नहीं देखें, दूसरे कामों में लगे रहें और अपने हल्के के लोगों की चिंता न करें तो उसका हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम आपको कल ही बाकायदा इस बारे में डेट भी देने की कोशिश करेंगे अगर हो सका तो आपको आज ही बता देंगे कि हमने किस किस हल्के में किस किस डेट को कितना कितना पैसा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बार बार बीच में बोलने के लिये क्यों खड़े हो जाते हैं इनकी यह बात अच्छी नहीं है। जब इनका नम्बर बोलने के लिये आएगा तो ये अपनी स्पीच में इन सारी बातों का उल्लेख कर सकते हैं। अगर कोई मैम्बर बोलते हुए आपके बारे में कुछ कह दें तब तो आपका फर्ज बनता है कि बीच में ही आप कह सकते हैं लेकिन यूं ही बीच में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिये। मैं बंसी लाल जी से भी कहूंगा कि वे तो बहुत ही सीनियर हैं इसलिये कम से कम उनको तो अपने इन चेलों को ठीक रखना चाहिये क्योंकि ये बीच में वैसे ही खड़े हो जाते हैं।

प्रो० राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, रांड तो रंडापा काट ले लेकिन रंडुए काटने नहीं देते। मुख्य मंत्री जी ने बंसी लाल जी से कहा कि अपने चेलों को ठीक रखें लेकिन ये उनको ठीक रहने तो नहीं देंगे क्योंकि ये उनको ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे वह ठीक नहीं रहते।

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने 17.60 किलोमीटर सड़कें बनायी हैं इन सड़कों की मरम्मत के लिये 15 करोड़ रुपये इस बार लगे हैं। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड आठ नौ करोड़ रुपये और लेकर स्पैशली टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कर रहा है। आज ही अमर सिंह जी ने बताया कि जितनी भी सड़कें टूटी हुई थीं उनकी युद्ध स्तर पर मरम्मत की जा रही है। अगर इस हिसाब से देखें तो लगता है कि वे काम करने के इच्छुक हैं और यह सब काम जारी है। इसके साथ ही मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जिसका राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किसानों की हालत सुधारने के लिये हमारे यहां पम्पिंग सैट्स हैं, मोनोब्लौक सैट्स हैं सबमर्सिबल सैट्स हैं इनके सारे टैक्स को माफ कर दिया। एक-एक किसान को अगर मोटर लेनी होती थी उसका

[साथी लहरी सिंह]

4-5 या 6 हजार रुपया किसान को टैक्स देना पड़ता था उस सारे टैक्स को माफ कर दिया है इससे सरकार पर कम से कम 100 करोड़ रुपये रेवेन्यू का फर्क पड़ता है इससे बढ़कर और क्या सबूत किसानों को फायदा देने का होगा। यह बाकायदा जो बात हुई है वह मैं बता रहा हूं। मैं राज्यपाल महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात का यहां जिक्र किया। व्यापारियों के लिये सारे कठिन फार्म्ज को बदल कर आसान फार्म बना दिए। व्यापारी पहले टैक्स की चोरी करना चाहते थे क्योंकि पहले फार्म बहुत कठिन थे। अब उन फार्मों को आसान कर दिया और टैक्स भी कम कर दिया अब सारे के सारे व्यापारी टैक्स देते हैं। टैक्स भरने का फार्म आसान करने के बाद सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आया है क्योंकि उन पर से इंस्पैक्टरी राज खत्म हो गया है। उन पर ज्यादा कागजी कार्यवाही को खत्म कर दिया है। टैक्स बैरियर भी खत्म कर दिए गए हैं। बैरियर खत्म करने के बाद सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा आया है। व्यापारियों ने टैक्स ज्यादा पे किया है। अब व्यापारी यह समझने लगा है कि जो टैक्स हम दे रहे हैं उसे देना हमारा फर्ज है। इससे ज्यादा बड़ा सबूत सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कराधान मंत्री जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आम आदमी की दुख की नब्ज को पकड़ कर देखा और उसका इलाज किया है। इसी तरह से मैं शराब के बारे में कहना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने सारे हरियाणा के गावों में पहली अप्रैल से शराब बन्द करने का फैसला किया है। (विघ्न)

डा० राम प्रकाश : शराब के ठेके बंद कराने के लिये हर बार संघर्ष होता था लेकिन कभी यह मांग नहीं मानी जाती थी। इस बार मैंने इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। (विघ्न)

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डा0 राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया। उस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए। अपोजीशन के भाईयों ने भी जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए हैं वे सरकार ने माने हैं इससे बड़ा सबूत सरकार दे नहीं सकती।

चौधरी बंसी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमीशन है कि सवा बारह बज गए हैं और कल गवर्नर साहब के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस भी होगी, जवाब भी हो जाएगा, वोटिंग भी हो जाएगी तो बोलने का मौका कब मिलेगा ? इसलिये मैं समझता हूं कि इसके लिये सैशन के कम से कम दो दिन और बढ़ाए जाएं ताकि सभी मैम्बर्ज अपनी बात कह लें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके फौरन बाद आपको ही मौका मिलेगा।

चौधरी बंसी लाल : अकेला मैं ही मैम्बर नहीं हूं, अपोजीशन के और भी मैम्बर हैं।

साथी लहरी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने बड़ी कृपा की है (विघ्न)।

श्री उपाध्यक्ष : लहरी सिंह जी, आप बड़े फारचुनिस्ट हैं कि आपके पीछे भी और दाएं बाएं भी प्रोफैसर बैठे हैं।

साथी लहरी सिंह : धन्यवाद सर। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कोआप्रेशन विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया है। इसने बेरोजगार युवकों को 50 हजार रुपये से एक लाख रुपए तक अपना काम करने के लिये कर्ज देने की सुविधा दी है। आज वे लोग जहां भी जाते हैं उनको फौरन कर्जा मिल जाता है चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई दुकानदार हो या कोई पढ़ लिख कर बेकार फिर रहा हो सभी को मिला कर हमारे करीब अढ़ाई लाख नव युवकों ने इस बात का लाभ उठाया है। उनके लिए इस विभाग ने 24 घंटे दरवाजे खोल रखे हैं। मैं इसके लिए बहिन शकुन्तला जी को मुबारिकबाद देना चाहता हूं। उन्होंने सहकारिता में बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने एक दरवाजे से सारी चीजें मुहैया करवाई हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पीछे पांच मुख्य मन्त्री इक्ट्ठे हुए थे। उनकी बात चीत से यमुना पर हथनी कुंड बैराज की शुरुआत हुई। आपको पता है कि इससे किसानों को कितना फायदा होगा। जब चौधरी बंसी लाल जी इस बात को कह रहे थे तो हम कहते थे कि दादूपुर नहर बननी चाहिए। तो ऐसे काम कागजों में नहीं बनते हैं ये तो मेहनत से बनते हैं। उस पर तीन साढ़े तीन करोड़ रुपए का काम होगा। उससे दादूपुर नहर भी निकलेगी। उससे वाटर लैवल भी ऊंचा हो जाएगा और किसान की हालत भी सुधरेगी। ये सारी बातें इस बात का सबूत हैं कि हम किस तरह से आम जनता को फायदा देने के लिये और उनको उन्नत करने के लिये कार्यरत हैं। तो यह सरकार नेक नीयत से काम कर रही है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पीछे हमने एक क्वैस्चन बहिन शान्ति राठी से पूछा था। तो मुख्य मन्त्री जी वहां गए और वहां पर एक परियोजना शुरु की गई। पहले यमुना नगर से लेकर इंदरी तक गन्दे पानी से लोग बीमार होते थे और डंगर भी मर जाते थे। तो एक स्कीम 133 करोड़ रुपए की यमुना नगर से शुरु की गई। इसके लिये मैं बहिन जी का आभारी हूं। राज्यपाल महोदय ने भी अपने ऐड्रैस में रादौर और इंदरी का जिक्र किया। इंदरी तो अपोजीशन का हल्का है फिर भी उन्होंने उसका नाम लिया। पहले घरौंडा तक जो प्रदूषण फैलता था उसको रोकने के लिये ट्रीटमैंट प्लांट लगाए जाएंगे तो इससे बढ़ कर सरकार क्या सबूत देगी। राज्यपाल महोदय ने जिस तरह से अपने ऐड्रैस में इन बातों का जिक्र करके सारी जनता को और हाउस को बताने की कोशिश की है वास्तव में ये सारी बातें आम आदमी के फायदे की बातें हैं। जो आदमी

[साथी लहरी सिंह]

आम आदमी का फायदा सोचेगा वह आदमी कभी मर नहीं सकता। गरीब आदमी की जो दुआ है वह किसी किसी को लेनी आती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आ गया और एक मिनट में ही किसी को थप्पड़ मार दिया और नाराज हो गया। लोगों को प्यार से, लोगों का विकास करके और लोगों को सभी सहूलियतें दे करके जो सेवा करेगा वही इस बात का भागी होगा। उसको वास्तव में आगे भी हिसाब किताब में क्रेडिट मिलेगा। मैं एक बात कहता हूं। जान है रहती नहीं मुझे संशय है जगह बनाई है नहीं बैठोगे कहां। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेते हुए कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पूरे सम्मान के साथ पास किया जाए। धन्यवाद।

Mr. Dupty Speaker : Motion moved—

That an address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 26th February, 1996."

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का पिछले साल का जो अभिभाषण था यह अभिभाषण भी उसी का रीपीटिशन है। बाढ़ तो उसके बाद आई इसलिये उसकी चर्चा होनी जरूरी थी। मगर वास्तव में इसमें कुछ है नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा 2 में लिखा है :—

"As you know, my Government had received the mandate in the general elections of 1991 on the plank of peace, development and just governance. I am happy to say that my Government has been eminently successful in fulfilling that mandate. The law and order situation in the State has been peaceful in the last five years."

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने तो यह भाषण पढ़ा है यह लिखा हुआ तो सरकार का ही है। मैं यह समझता हूं और सारा हरियाणा प्रदेश यह समझता है कि हरियाणा प्रदेश में जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है It is far from satisfaction. There is no law and order.

यहां रेप होते हैं और छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको मार भी दिया जाता है। लड़कियां उठा भी ली जाती हैं, पता भी नहीं लगता। हिसार में सुशीला कांड 1991 के बाद ही हुआ, द्रोपदी कांड भी 1991 के बाद ही हुआ, रेणुका कांड भी 1991 के बाद ही हुआ।

अभी पिछले दिनों एक और कांड हुआ उसका उषा नाम था या कोई और नाम था। महीने पहले रोहतक से एक लड़की उठाई जिसका आज तक पता नहीं है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक लड़की रोहतक में स्कूल को जा रही थी। जैसे ही वह लड़की स्कूल को जाने लगी दो गुण्डे उस लड़की पर झपटे और वह लड़की भाग कर वापिस घर में घुस गई। घर वालों ने कहा कि लड़की को कल स्कूल भेजेंगे। उस लड़की के घर वालों ने इस घटना के बारे में सभी मौहल्ले वालों को बताया और उन्होंने मोहल्ले वालों को कहा कि हम लड़की को कल स्कूल भेजेंगे। वह दोनों गुण्डे गलियों में घूमते रहे। मोहल्ले वालों ने उस लड़की के घर वालों को कहा कि कल आप लड़की को स्कूल भेजना उस समय हम अपने घरों के आधे आधे दरवाजे खोल कर खड़े रहेंगे। जब दूसरे दिन लड़की स्कूल जाने लगी तो लड़की का बाप हाथ में लाठी लेकर उसके पीछे पीछे चला। तभी दो गुण्डे उस लड़की पर झपटे लड़की ने शोर मचाया। सारे मोहल्ले के लोगों ने उन दोनों गुण्डों को पकड़ लिया। एक गुण्डा तो उसी वक्त छुड़ा कर भाग गया। दूसरे को मौहल्ले वालों ने पकड़ कर रखा। यह खास रोहतक शहर की बात है। वहां पर जो लोग थे उनमें से किसी एक आदमी ने किसी दूसरे को टेलीफोन किया कि भाण्डा फूट गया। वहां पर मोहल्ले वालों के कहने के कारण दो पुलिस के जवान भी साधारण वर्दी में आये हुए थे। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब अगले दिन एक गुण्डे को जो मौहल्ले वालों ने पकड़ा था और जिसे पुलिस ले गई थी अदालत में पेश किया तो पुलिस ने उसका पुलिस रिमांड कोर्ट से नहीं लिया और दूसरे को गिरफ्तार नहीं किया। तीसरे आदमी ने चौथे आदमी को टेलीफोन किया कि भाण्डा फूट गया उनको गिरफ्तार नहीं किया। इसी प्रकार से प्रो० रण सिंह सुहाग का भी केस है। यहां पर एक नहीं सैंकड़ों ऐसी वारदातें हुई हैं। फिर भी राज्यपाल महोदय कहते हैं कि मेरी सरकार ने ला एण्ड आर्डर की स्थिति को सुधारा है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों यानि 7—8 महीने के अंदर-अंदर हिसार के एस० एस० पी० व ए० एस० पी० और एक एस० एच० ओ० को सजा सुप्रीम कोर्ट से हुई। जब वे कैद काट कर वापस आये तो सरकार ने फिर उनको ड्यूटी पर ले लिया। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि सजा काटे गए अधिकारियों को पुनः कैसे नौकरी में ले लिया गया। क्या सरकार इस तरह में गई कि क्यों उनको सजा हुई ? जिन आदमियों को उठाने के कारण केस सुप्रीम कोर्ट में गया और उनको सजा हुई तो कृपया मुख्य मन्त्री जी अपने जवाब में बता दें कि क्यों उनको सजा हुई और क्यों उन लोगों को रास्ते में से उठाया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पिछले दिनों रेलवे पुलिस के भी एक कप्तान को अभी हाल ही में एक साल की सजा हुई है और वह सजा काट रहा

[चौधरी बंसी लाल]

है। फिर भी राज्यपाल कह रहे हैं कि प्रदेश में मेरी सरकार ने ला एण्ड आर्डर की स्थिति में सुधार किया है । मैं जानना चाहूंगा कि इतने कांड हो जायें तो फिर खराब स्थिति कौन सी हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, यह सारे हिन्दुस्तान में एक मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट से 3–3 आई0 पी0 एस0 को सीधी सजा हो। यह कोई छोटी और साधारण बात नहीं है । इन बातों को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। इसकी गहराई में सरकार को जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय ने बोलते हुए कहा कि मेरी सरकार द्वारा the most significant thing in the rule of law was established in the minds of the common men in the State.

कौमन मैन की बात करके देखें तो स्टेट में राज ही नहीं है, जो कर ले वही ठीक है । जब खेत के रखवाले ही खेत को खा रहे हैं तो खेत का मालिक भगवान ही है । पुलिस लोगों की रक्षा के लिये होती है अगर पुलिस ही लोगों की भक्षक हो गई तो फिर रूल आफ ला कहां है ? अध्यक्ष महोदय, मुझे तो पूरे प्रदेश में कहीं पर भी रूल आफ ला नहीं लगता । गवर्नर साहब ने यह भी फरमाया है :—

> "A responsive administration, progressive development policy, welfare of weaker sections and social justice have been the hallmark of the policies of my Government."

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले पौने पांच साल से इनकी सरकार आई है, कुल कितने मुलाजिम रखे गए हैं, पुलिस की टोटल कितनी भर्तियां हुई हैं, कितने लोगों को भर्ती किया गया है, पोस्टों की पब्लिसिटी कहां कहां और कैसे की गई है कौन-कौन से अखबार में, किस-किस मीडिया पर यानि कि रेडियो या टी0 वी0 पर या कहां कहां पर एडवरटाईजमैंट दी गई और उनमें से कैसे कैसे भर्ती की गई । मैं मुख्य मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि एक व्हाइट पेपर ईशू करें जिसमें पुलिस मुलाजिमों की भर्ती का ब्यौरा हो, उनके परमानैंट एड्रैसिज हों और यह भी वर्णन हो कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा कहां से पास की है । दसवीं के सर्टिफिकेट से असली रिहाईश का पता चलता है । 1700 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जो बात है उसके बारे में मैंने अभी हाईकोर्ट की जजमैंट तो नहीं पढ़ी है लेकिन अखबार में पढ़ा है । "नवभारत टाईम्ज" में पुलिस की भर्ती के बारे में छपा है और दूसरे अखबारों ने भी पुलिस भर्ती में फेवरेटिज्म और नैपोटिज्म के बारे में लिखा है । अध्यक्ष महोदय, आज सवेरे मेरे पास मेरे एक साथी का टैलीफोन आया और उसने नवभारत टाईम्ज में छपी न्यूज के बारे में मुझ से

जिक्र किया। "अपार दर्द और गुस्सा छिपा है उनके दिलों में" इस शीर्षक से यह छपा है जिसे मैं पढ़ देता हूं :—

रोहतक 26 फरवरी।

"इब और के कर हैंगे, बिचौलिए त पकड़ेंगे, रपइए लेंगे अर भाईचारे में माह दिए तो हांगेह ते लेंगे। रपइए छोड़ड़ै कोण्याह, चालीस हजार पूरे दे राक्खे सैंह, नाह रपया बाध अर नाह घाट।" ये शब्द हैं महम के राकेश कुमार के जिन्हें हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले के बाद पुलिस के सिपाही के रूप में अपना प्रशिक्षण अधूरा ही छोड़ कर घर वापस लौटना पड़ा है। याद रहे कि उच्च न्यायालय ने गत दिनों अपने एक निर्णय में हरियाणा पुलिस के 1700 कर्मियों की भर्ती को रद्द कर दिया था। न्यायालय के फैसले के बाद अब प्रशिक्षणरत सैंकड़ों पुलिस-कर्मी अपने घरों में लौट आए हैं।

राकेश कुमार ही अकेले ऐसे युवक नहीं हैं जिन्हें उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के बाद घर वापस लौटना पड़ा। सतबीर, राजकुमार, संजय, विनोद और सुनील भी उन्हीं 1700 अभागे युवकों में से हैं।

सतबीर ने नभाटा को बातचीत में कहा, "भाई साहिब, कैसे भर्ती हुए थे और कैसे नहीं ये बातें बताने की नहीं होती फिर भी आप अखबार वाले हो और घर आए हो तो बतानी पड़ैगी। तीन जगहों से पैसा उठाया था और वह भी 3 (तीन) रुपए सैंकड़ा ब्याज पर। पूरे पैंसठ हजार दिए थे। पर केह बेरा था अक न्यू बणैगी। भगवान इसी किस्से केह साथ नाह करयो अब क्या करोगे "इबकी इब देखी जाएगी हल जोड़ेंगे अरै जिसके लें राक्खे सै देहंगे।"

राजकुमार की भर्ती होने की व्यथा कथा सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं चार बहनों के इकलौते भाई राजकुमार ने 'नभाटा' से बातचीत में कहा, "जेह सच्ची है पुच्छो तो बाक्की किमह सै नही," पर पार किमह बसाती नहीं। मेरी मां ने टूम (आभूषण), गहणे (गिरवी) धर के भर्ती करवाया था, अर बटेऊ के देणे सै न्यारे, भून्डी ए बणी सेहें भाईसाहब।" अब क्या करने का बिचार है ?" "आत्मा की बात जानना चाहो ना तो बात न्यूह सै अक एक लेहके रिवाल्वर अर पांच चार केह माह ते कट्ठी ए काढ़ दूंयं। अर फेर की फेर देखी जागी।

यह आज के नव भारत टाइम्स में लिखा हुआ है। यह कोई बनावटी बात नहीं लगती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जब ऐसी बातें प्रदेश में हो रही हैं और राज्यपाल महोदय, कहते हैं "रूल आफ़ लॉ रिस्पेक्टिव

[चौधरी बंसी लाल]

गवर्नमैंट है तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह जो पुलिस में 17 सौ आदमियों की भर्ती हुई है इस बारे में मुख्यमन्त्री जी पूरा ब्यौरा दें कि वे कहां-कहां के हैं और इनमें से कितने एस0 सी0, बी0 सी, इत्यादि हैं अगर ये यह लिस्ट दे देंगे तो गवर्नर साहब को इसके लिए कुछ क्रैडिट मिलेगा।

आगे राज्यपाल महोदय, कहते हैं कि —

> "The law and order situation in 1995 was peaceful throughout the State and the common man lead his life with a sense of security.'

औरतों की बात तो मैंने अभी बताई है और जहां तक वीकर सैक्शन की बात है तो उनको इन्साफ मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। अदालतों में चले जाएंगे तो फैसला बहुत देर से होता है और वकील भी बहुत पैसा मांगते हैं जिस वजह से उनको इन्साफ मिलना आज बहुत मुश्किल हो गया है। Further it has been stated—

> "My Government has taken several steps to strengthen and modernise the State police force."

अध्यक्ष महोदय, चाहे कितनी भी माडर्नाईजेशन कर दी जाए, यह अच्छी बात है कि माडर्नाईजेशन होना चाहिए, चाहे ये अच्छे तरीके अख्तियार कर लें वह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जो लोग पैसा देकर भर्ती हुए हैं वे काम कैसे इमानदारी से करेंगे। वे कहां से तीन रुपया सैंकड़ा का ब्याज चुकाएंगे, वे कहां से उनकी माताओं ने जो गहने गिरवी रखे हैं उनको छुड़वाएंगे। It has also been stated—

> "The recruitment of women in the police force has also been stepped up."

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि लड़कियों और औरतों को पुलिस में भर्ती करने का क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मोड होगा। ये इस बारे में जब जवाब दें तो हमें बता दें।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण के पैरा नं0 4 में कहा है कि—

> "Normal life was badly disrupted in many parts of the State, due to unprecedented floods of 1995. The flood caused severe damage to private and public property and resulted in deaths of 167 human beings and thousands of cattle. The terrible incident of fire at Dabwali on 23rd December, 1995 claimed the lives of hundreds of

children and their guardians etc.'

राज्यपाल महोदय, ने यह बात ठीक कही है कि 1995 में बहुत भारी, बाढ़ आई लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता हूं कि बाढ़ में यमुना नगर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, और महेन्द्रगढ़ सब जिले डूबे हुए थे। मैंने वहां का दौरा किया था। पहले 15 दिनों तक सरकार को वहां के बारे में कोई सूझ नहीं थी कि वह क्या करे। अध्यक्ष महोदय, मैं जहां पर भी गया वहां सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं था। बाढ़ से निपटने के लिये हर जिले में एक कमेटी होती है, डिप्टी कमीशनर उसका मैम्बर होता है, मुख्यमन्त्री जी उस कमेटी के चेयरमैन होते है और वह कमेटी 15 जून से पहले पहले अपनी फाइनैंशियल पोजीशन के बारे में रिपोर्ट भेजती है। यह कमेटी यह निर्णय लेती है कि बाढ़ रोकने के बारे में सारे ऐक्शन ले लिए गए हैं और अब बाढ़ नहीं आएगी। दो साल पहले भी जब कैथल और सिरसा में बाढ़ आयी थी तो हमने इसी सदन में सरकार को कहा था कि अगर आप इस बाढ़ को रोकने का प्रबन्ध नहीं करोगे तो आगे और भी ज्यादा नुकसान होगा। उस समय मुख्यमन्त्री जी ने हमें विश्वास दिलाया था कि आईंदा से बाढ़ से कोई नुकसान नहीं होगा। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस स्टेट में जितनी भी ड्रेन्ज है, हालांकि उस वक्त तो उनमें पानी था, मगर हमने उस वक्त भी मुख्य मन्त्री जी से कहा था कि पेहवा के पास जो सरस्वती ड्रेन है आप उसे देख लें उसी तरह से कैथल की भी ड्रेन आप देख लें। उन ड्रेनों में 18-18, 20-20 फुट की कीकर खड़ी हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, एक और घास होती है जिसे करनाल, अम्बाला और यमुनानगर साईड के लोग समुद्र सोख कहते हैं जो कि मोटे पत्तों की होती है और फरीदाबाद गुड़गांव के लोग उसको जल खुम्भी कहते हैं यह दो दो फुट ऊंची होती है जो बिल्कुल भी पानी आगे नहीं चलने देती। इसके अलावा उन ड्रेनों में बुशिज भी खड़ी थी झाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन सरकार की तरफ से उन ड्रेनों की सफाई नहीं की गयी जो जैसी थी वह वैसी ही पड़ी रही। किसी भी ड्रैन में से इन्होंने एक कस्सी मिट्टी नहीं निकाली। अगर मुख्यमन्त्री जी चाहें तो इसी सदन की एक कमेटी लेकर होली की जो चार दिन की छुट्टी है, उनमें हमारे साथ चलें हम इनको वह ड्रेन दिखा देंगे जो हम देखकर आए हैं। बाढ़ की वजह से रोहतक में भारी तबाही हुई है। उस तबाही से रोहतक का पानी, सोनीपत का पानी ड्रैन नं0 6 जिसको एस्केप ड्रेन भी कहते हैं में डाल सकते थे इसी तरह से ड्रेन नं0 8 के द्वारा भी वह पानी निकाला जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, अगर आप आज ड्रेन नं0 8 को देखें या मुख्यमन्त्री जी भी उसको देखें तो यह पाएंगे कि उस ड्रेन की किसी भी जगह से कभी

[चौधरी बंसी लाल]

कोई मिट्टी पिछले चार पांच सालों में नहीं निकाली गयी है जिसके कारण उस ड्रेन की कैपेसिटी आज वन थर्ड से ज्यादा नहीं रह गयी है। आज आप किसी भी ड्रेन को देख लें उनमें दरख्त टूट टूट कर गिर गए हैं जो पानी को आगे नही चलने देते। अध्यक्ष महोदय, आप भी अगर सुनेंगे तो हैरान होंगे तथा अगर मुख्यमन्त्री भी रोहतक से हिसार जाते हुए ड्रेन नं0 8 के पुल पर खड़े होकर बांयी ओर नजर डालें तो इनको पता लगेगा कि उस ड्रेन की कैपेसिटी शायद ही एक चौथाई रह गयी हो। आज ड्रेन नं0 8 की यही हालत है। इसी तरह से उस ड्रेन का जो पानी दादरी के इलाके में खैरड़ी मोड़ से लेकर रानीला गांव तक गया है उसकी वजह से ये गांव बाढ़ के पानी से डूब गए हैं बाकी जगहों पर तो पानी उतरकर पहुंचा है लेकिन अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात तो यह है कि इन्दिरा गांधी कैनाल या लौहारू कैनाल पर धिकेड़ा पम्प हाउस पर 32 या 38 पम्प लगे हुए हैं परन्तु कभी भी सात या आठ से ज्यादा वे पम्प नहीं चले। केवल एक दिन 12 पम्प चले थे। वह भी कुछ ही घंटों के लिये ही चले थे। आप ही बताएं कि फिर पानी कहां से निकलेगा। अगर जे0 एल0 एन0 के पम्प साफ होते तो रोहतक का सारा पानी निकल जाता और वह पानी आगे महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के इलाकों में चला जाता जहां पर फसल सूख गयी। अगर वह पानी वहां चला जाता तो उस फसल को भी पानी मिल जाता। जो लोग पहले पानी से डूब गए थे उनको भी उस पानी से छुटकारा मिल जाता। इसी तरह से यही हालत आज लौहारू कैनाल की हुई है। यही हालत जे0 एल0 एन0 की हुई है जबकि सरकार कहती है कि हमने सारा पानी निकाल दिया है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जरा मुख्यमन्त्री जी दिल्ली से रोहतक जाकर देख लें तो यह पाएंगे कि सांपला से पहले और बाद में भी दोनों जगहों पर पानी खड़ा हुआ है। इसी तरह से आप रोहतक से हिसार चले जाएं तो वहां भी दोनों तरफ पानी खड़ा है। इसी तरह से नेशनल हाइवे नं0 10 तीन महीनों से भी ज्यादा समय तक बन्द रहा। यह रोड एक स्ट्रैटजिक रोड है जो कि मिलट्री को मूव करने के लिये है। इसी रोड से मिलट्री फाजिल्का बोर्डर तक पहुंचती है परन्तु तीन या साढ़े तीन महीने तक यह रोड बन्द रही। भगवान न करें परन्तु अगर इस दौरान ऐसी कोई आपदा आ जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। नेशनल हाईवे को ये नहीं खोल सके और तीन किलोमीटर लम्बाई में उस पर पानी खड़ा रहा। अब भी वहां जाम लगते हैं। रोहतक से भिवानी चले जाएं रास्ते में दोनों तरफ पानी खड़ा है। भिवानी से दादरी के रास्ते में पानी खड़ा है। दादरी के पास जयश्री गांव है वहां आज भी 4 फुट पानी खड़ा है। कैथल से जींद के रास्ते में पानी खड़ा है सरकार उस पानी को निकालने की कोशिश तो करे। बालू रेत जहां पर

थी वहां पानी खड़ा रहने से दलदल बन गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए से कहूंगा कि सरकार अच्छे ऐक्सपर्ट बुलाए और उस पानी को निकालें जहां जहां दलदल बन गई है और जहां पानी से जमीन कल्लर हो गई है उस जमीन को री-क्लेम करने का प्रबन्ध करें नहीं तो स्टेट को भी नुक्सान है देश को भी नुकसान है और किसान को तो है ही। यह जो चीजें हैं यह सोच विचार करने की है। बाढ़ का जो नुकसान था, उसका जो मुआवजा बंटा उसमें किसी व्यक्तिगत केस की मैंने इंक्वायरी नहीं की लेकिन मुझे रोहतक में और अन्य जगहों पर बताया गया कि जिसका कोई नुकसान नहीं है उसको भी पूरा पैसा मिल रहा है और जिसका पूरा नुकसान है उसको एक धेला भी नहीं मिला। इस प्रकार यह जो मुआवजे का वितरण हुआ है वह गलत हुआ है मुख्यमन्त्री जी ने उस समय कहा था कि 600 करोड़ रुपये की सहायता भारत सरकार ने दी है अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आ गया कि इस 600 करोड़ में से 39 करोड़ 41 लाख रुपया तो ग्रांट है और 570 करोड़ रुपया कर्जा है। सरकार को यह कर्जा भी देना पड़ेगा और उस पर 13 परसैन्ट ब्याज भी देना पड़ेगा। इस प्रकार हर साल 100 करोड़ रुपया और साथ ही उस पर 13 परसैन्ट ब्याज देना पड़ेगा। मुख्यमन्त्री जी ने कहा इसका प्रोविजन किया है यह भी बताने की कृपा करेंगे। बाढ़ के बारे में तो और साथी भी बोलेंगे। मैं समझता हूं कि जींद, कैथल, भिवानी, रोहतक और हिसार जिलों में तो बाढ़ ने इतनी तबाही की है कि वहां के लोग कई सालों तक उबर नहीं पाएंगे। उन्हीं जगहों पर जहां बाढ़ आई थी अब 3-4 दिन पहले ओले पड़ गए हैं। वहां पर जो थोड़ी बहुत फसल थी वहां ओले पड़ गए। जहां ओले पड़े हैं वहां के किसानों को फौरी तौर से राहत दी जाए क्योंकि उनको डबल मार पड़ चुकी है। ओले जो पड़े हैं वह दादरी सब डिवीजन में बौंद कलां, बौंद खुर्द, रानीला, रणकोली, मोलपोस, नीमली, रायकोली और कैथल जिले में भी पड़े हैं। सरकार पता करके उन किसानों को राहत दे। इसकी रिपोर्ट तो मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी के पास हर रोज शाम को आ जाती है कि कहां ओले पड़े हैं और कितना नुकसान हो गया। जहां-जहां पर ओले पड़े हैं अगर उनको फौरी तौर से सहायता मिल जाए तो वे किसान अपने आप को कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा 5 में कहा है—

> "My Government is fully prepared to discharge its consitutional and moral responsibility to conduct a fair and peaceful poll."

इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जो पंचायत समितियों, जिला परिषदों और लोकल बाडीज के इलैक्शन हुए उन्हीं में सरकार ने रिजल्ट एक तरफा डिक्लेयर करा दिए तो इन इलैक्शनों में क्या उम्मीद रखें। मैं समझता हूं कि इसका कोई तरीका

[चौधरी बंसी लाल]
रखें जिससे फेयर इलैक्शन हो सकें। मुझे फेयर इलैक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। राज्यपाल महोदय कह रहे हैं —

> "It is time for us to work committedly for the establishment of a clean image and value-based politics in public life."

तो क्या यह जो सब चल रहा है यह गवर्नर महोदय के ध्यान में नहीं आया। इन्होंने तो जो लिखना था वह लिख दिया लेकिन उनको तो इसे पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए था। In the Governor's Address, it is mentioned—

> "This will go a long way in strengthening the freedom and ideals that we have inherited through the sacrifice of our forefathers during the freedom struggle."

अध्यक्ष महोदय यानी फ्रीडम स्ट्रगल का राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया। यह हमारे इस सदन का सबजैक्ट नहीं था लेकिन पिछले दो दिन से अखबारों में जो कहानी आ रही है कि एक एम0पी0 का वोट डालने के बाद तीसरे दिन बैंक में तीस लाख रुपया जमा हो गया। मुख्य मन्त्री जी को याद आना चाहिए कि उस वक्त अखबारों में आया था कि चौधरी भजन लाल ने कहा है कि नरसिम्हा राव की सरकार मैंने बचाई है। इसलिए कहीं आप तो यह काम करने वाले नहीं थे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा वरना यह बात पेपरों में छप जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने उनकी सरकार बचाई है। ये तो अपने मुंह से कह सकते हैं कि मैंने बचाई थी। दूसरी बात जो तीस लाख रुपए देने की अखबारों में आई है उसका इस सदन से और भजन लाल से कोई ताल्लुक नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : मैं तो खुद कह रहा हूं कि यह मामला हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं आता कि एक मैम्बर के वोट देने के दो तीन दिन बाद तीस लाख रुपया उसके खाते में बैंक में जमा हो गया। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और है अगर मैं इस बारे में ज्यादा कहूंगा तो मेरे और मुख्य मन्त्री के बीच थोड़ी बद मजगी हो जाएगी। इसलिए मैं हिसाब की बात कहना चाहता हूं। एक इन्होंने कहा कि—a well planned road transportation system तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसा इरादा रखती है तो अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है कि यह कागजों तक ही रहेगा और उससे आगे बढ़ने का सरकार का इरादा नहीं है। आज हम यह कह सकते हैं कि सड़कें एक ऐसी चीज हैं जिसके ऊपर देश की इकोनमी निर्भर करती है। इनका देश की इकोनमी में बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी कन्ट्रीब्यूशन है। अध्यक्ष महोदय, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो ट्रैफिक रूटस हैं

उनके ऊपर मरम्मत का काम तो शुरु कर रखा है लेकिन वह कब तक पूरा होगा उसके बारे में कहा नहीं जा सकता । जो एप्रोच रोडज हैं जिनके द्वारा किसान अपने घर से मंडी तक अनाज लाता है वे कब तक ठीक होंगी । अध्यक्ष महोदय, बाकी जो सड़कें हैं उनकी पहले भी कभी मरम्मत नहीं हुई जो वे थोड़ी बहुत ठीक थीं उनको बाढ़ ने तोड़ डाला । उनकी बहुत बुरी हालत है । रोडवेज के बारे में मैं बाद में कहूंगा । इसमें सड़कों की मरम्मत के बारे में कहा गया है । इस बारे में तो मेरा ख्याल है कि सरकार भी जानती है और हम और आप भी जानते हैं कि सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है । ये सड़कें न हो कर मोटर ट्रेकर बन गई हैं । जो नेशनल हाई-वे नं० 1 रोड है यह दिल्ली से ले कर अम्बाला तक हमारे प्रदेश में है । इस सड़क पर कई सालों से फोर लेनिंग का काम चला हुआ है । कुरुक्षेत्र से 10–15 किलोमीटर इधर उधर चार पांच महीनों से तेजी से काम हुआ है लेकिन मधुबन से लेकर चक्रवर्ती लेक तक का जो काम है वह सब से ज्यादा जरूरी है । वहां पर रोजाना एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन वहां पर काम धीमा है । मुझे लगता है शायद वह काम होने के आसार नहीं हैं क्योंकि करनाल शहर के बाईपास की कुछ पुलियां कई सालों से बनी पड़ी हैं लेकिन उनका मिट्टी का काम आज तक शुरू नहीं हुआ है । मैं समझता हूं कि उस काम को वार फुटिंग पर कराया जाना चाहिए वरना काम नहीं चलेगा । उसके बगैर लोगों को बड़ी भारी दिक्कत है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा नम्बर 9 में सिंचाई एवं बाढ़ के बारे में कहा है । बाढ़ की बात तो मैं कह चुका । अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के अन्दर जितनी भी नहरें हैं आप चाहे किसी भी नहर पर चले जाएं सभी नहरों के अन्दर दोनों तरफ झाड़ खड़े हैं उनके कारण पानी के चलने में बहुत रुकावट है । किसी भी नहर की सफाई नहीं हुई है । किसी भी नहर की डीसिल्टिंग नहीं हुई है । मेरी इतलाह के मुताबिक नरवाना ब्रांच की कैपेसिटी सफाई न होने के कारण एक हजार से 1500 क्यूसिक्स तक कम है वह महज इसलिए है क्योंकि उसकी प्रोपर मेंटीनेंस नहीं है, उसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई है । मैं यह कहना चाहूंगा कि एक हजार से 1500 क्यूसिक्स कैपेसिटी कम होने का मायना है कि स्टेट को उसका बड़ा भारी नुक्सान । आप पंजाब वालों के साथ उसके बारे में बात करें और उनको पैसा दे करके उनसे भाखड़ा मेन लाईन की डीसिल्टिंग करवाएं और उसके दोनों तरफ जो बीड पैदा हो गए हैं उनको निकलवाएं ताकि पानी चलने में कोई रुकावट न हो । एक हजार क्यूसिक्स से 1500 क्यूसिक्स पानी कोई कम नहीं होता है बहुत होता है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा नम्बर 11 में कहा है :—

> "I am happy to announce that my Government has taken a revolutionary decision towards prohibition, namely that no liquor vends will be opened in the rural areas of Haryana next year."

[चौधरी बंसी लाल]

मैं समझता हूं यह आई बात है। शराब के ठेके शहरों में भी बन्द होने चाहिएं। अगर आप गांवों में नहीं खोलेंगे तो लोग गांवों से शहरों में आ कर शराब पी कर लौटते फिरेंगे। आप प्रदेश में शराब टोटली बन्द कर दो ताकि कोई झगड़ा न रहे। इसको आप बिल्कुल ही बन्द कर दें, शहरों में भी यह क्यों रहे। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा नम्बर 13 में फिर कह दिया कि मेरी सरकार ने बाढ़ के दौरान लोगों को इमिजिएट रिलीफ दिया। इस बारे में मुझे थोड़ा और बोलना पड़ेगा क्योंकि इस बारे में इसके अन्दर एक पैरा और लिख दिया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने रोहतक में एक डी0सी0 फ्लड लगाया। उसको हम पांच आदमी मिलने के लिए गए। मैं था और मेरे साथ सेठ श्रीकिशन दास, ओम प्रकाश बेरी, मनफूल सिंह और राजीव हम पांच आदमी उस डी0सी0 से मिलने गए। इससे एक या दो दिन पहले सेठ श्रीकिशन दास उस डी0सी0 से मिलने गए। यह भी माना हुआ फैक्ट है कि बाढ़ के दौरान सेठ श्रीकिशन दास ने रोहतक में राहत के बहुत जबरदस्त काम किए। जब हम उस डी0सी0 से मिलने गए तो उस समय वहां उनसे जो आदमी बात कर रहे थे उनका फ्लड से कोई मतलब ही नहीं था। हम पौना घंटा बैठ कर वहां से वापिस आ गए। अगले दिन फिर हम सब उसडी0सी0 के पास गए। हमने उनसे बात की कि आप इस पानी को निकलवाएं। उन्होंने कहा कि इस पानी को निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है कहां पर निकलवाऊं। हम तो उससे पानी निकलवाने की बात कह रहे थे और वह डी0सी0 कहता है कि मेरे पास पांच लाख रुपए का मोमबत्तियों का बिल आ गया। हमने कहा कि हम मोमबत्तियों की बात करने नहीं आए। हम तो यह बाढ़ का पानी निकलवाने की बात करने आए हैं। हम से आप यह पानी निकलवाने की बात करें। सेठ श्रीकिशन दास ने बताया कि ड्रेन नम्बर 8 में पानी के डिस्पोजल के दो नाले जाते हैं यह पानी आप उनमें डाल दें। सेठ श्रीकिशन दास ने उनको बताया कि खोखरा कोट के बाईपास के परली तरफ 20–20 और 25–25 फुट गहरे गड्ढे हैं यह पानी उनमें डाल दें। इसके अलावा उन्होंने उनको दो तीन और रास्ते भी बताए। एक रास्ता यह भी बताया कि शहर से पानी निकाल करके जे0एल0एन0 तक एक किलोमीटर लम्बी ड्रेन खोद कर पम्प करके उस पानी को जे0एल0एन0 में डाल दें। जे0एल0एन0 के पम्प ही इन लोगों ने नहीं चलाए अगर ये उन पंपों

13.00 बजे | को चलाते तो पानी निकल जाता। डी0सी0 ने कहा कि मैं अभी वहां पर देख कर आया हूं जो आप डिस्पोजल के दो नाले बता रहे हैं उनमें ड्रेन नं0 8 से पानी बहकर शहर की तरफ आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है। सेठ श्री किशन दास ने वहीं कहा कि मैं अभी आधा घण्टा पहले ही वहां से आया हूं पानी आगे की तरफ जा रहा है। खैर वह रिपोर्ट तो डी0सी0 के पास थी और खोखरा-कोट के पास जो गड्ढे थे उनके बारे में डी0सी0 ने कहा कि उनमें पानी नहीं डाल सकते। जब डी0सी0 ने हमारी बात नहीं मानी तो हम पांचों आदमी वहां से

उठकर बेरी साहब भी थे, ये यहां पर बैठे हैं तो हम वहां चले गए जहां से उन दोनों डिस्पोजल के नालों का पानी जाता है। हमने वहां पर जाकर देखा तो बहुत तेजी से पानी आगे की तरफ ड्रेन नं0 8 की तरफ जा रहा था। जो बातें डी0सी0 महोदय ने बताई वह सच नहीं थी। अलटीमेटली पानी वहीं खोखराकोट में डालना पड़ा जिसके बारे में सेठ श्री किशन दास ने सुझाव दिया था। सरकार तो आना-कानी कर रही थी और वहां पर जो एक किलोमीटर ड्रेन जे0एल0एन0 तक खोदनी थी वह खोदी गयी थी या नहीं, इस बात का तो मुझे इलम नहीं। महीने तक तो कुछ नहीं हो रहा था, कह कर ही रह गए किसी ने कुछ किया नहीं। रोहतक में आप देखें तो अब भी मोहल्लों के कई रिहायशी प्लाटों में बाढ़ के समय का पानी खड़ा है, अभी तक निकला नहीं है जिस कारण वहां की आस पास की बिल्डिंगें डैमेज हो रही हैं। उस पानी को आप अभी निकलवायें। वे बहुत से गरीबों के मोहल्ले हैं। मैं सरकार से आपके जरिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस पानी को निकालने का तुरन्त प्रबन्ध करें।

In para 13, it has been stated—

> "Air dropping of food, medicines and drinking water was resorted to for a week in the affected areas of Rohtak, Bhiwani and Hisar districts."

अध्यक्ष महोदय, बाद में हम दुजाना गये। वहां पर पहुंचने पर हमने लोगों से पूछा कि एयर ड्रोपिंग से आपके पास खाना आया। लोगों ने हमें बताया कि एक हैली-काप्टर आया था और वह 5 से 15 पैकेट के बीच गिरा कर गया था but certainly it was below 20 packets. फिर हम बेरी में गए। लोगों ने बताया कि वहां पर एक हैलीकाप्टर आया था और वह 500 के करीब पैकेट डाल कर गया था। आप जानते हैं कि बेरी कस्बा बहुत बड़ा है। दुजाना तो टोटली हरिजनों की आबादी वाला गांव है। बाढ़ के पानी के बारे में मैं आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां-जहां पर पानी खड़ा है वहां से उस पानी को तेजी से निकाला जाए और जमीन पानी के खड़ा रहने के कारण खराब हो गई है उसको रिक्लेम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पैरा नं0 16 में राज्यपाल महोदय ने एस0वाई0एल0 नहर के बारे में कहा है—

> "With a view to protecting the interest of the State, my Government has now filed a petition in the Supreme Court seeking completion of construction of the canal. We are hopeful that this issue will be decided soon and Haryana would be given justice."

अध्यक्ष महोदय, 1991 में जब इस सदन का पहला सैशन हुआ तो मुख्य मन्त्री जी ने यहां सदन में कहा था कि एक साल के अन्दर-अन्दर एस0वाई0एल0 नहर बन कर

[चौधरी बंसी लाल]

तैयार हो जाएगी । ये हर साल एक साल कहते रहे और अब पौने पांच साल हो गए लेकिन नहर नहीं बनवा सके । अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए । मैं कहना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में गए, यह किसका फैसला था । कानून के हिसाब से जो वाटर ट्रिब्यूनल फैसला कर दे उसकी अपील कहीं पर लाई नहीं करती । वैसे हमें यह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस से हरियाणा को हरियाणा का हक मिलेगा लेकिन वह हक दिलवायेगा कौन ? आज केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकारें हैं । दिल्ली की केन्द्र सरकार को भी पौने पांच साल हो गए । मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पानी को दिलवायेगा कौन ? आज की भारत सरकार क्यों नहीं हमें उस पानी को दिलवाती ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । चौधरी बंसी लाल जी ने इस केस को या तो पूरी तरह से पढ़ा नहीं है या फिर इसके पूरे तथ्यों की इनको जानकारी नहीं है । हम पानी के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए हैं बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन्ज लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं । ट्रिब्यूनल ने जो फैसला किया है उसकी अपील नहीं हो सकती । न तो उसमें पंजाब गवर्नमैंट अपील कर सकती है और न ही हरियाणा गवर्नमैंट अपील कर सकती है । हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गए हैं कि हरियाणा में नहर 10-12 साल से बनी हुई है और खाली पड़ी है, इसलिए मेहरबानी करके डायरैक्शन दीजिए कि 9 महीने में इस नहर को या तो पंजाब सरकार बनाए या भारत सरकार बनाए । अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इस नहर को हरियाणा के हवाले करिए ताकि हरियाणा सरकार नहर खुद बनवा सके । स्पीकर साहब, जब सुप्रीम कोर्ट से डायरैक्शन्ज होंगी तो फिर यह नहर हर सूरत में बनानी पड़ेगी ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, हमें इस बात का पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में ये किस लिए गए हैं । इन्होंने इस बात को साफ कर दिया, यह अच्छी बात है । सुप्रीम कोर्ट ही कोई डायरैक्शन कर दे ताकि नहर बन सके । जब सुप्रीम कोर्ट डायरैक्शन देगी तब तो पंजाब सरकार या भारत सरकार इस नहर को कम्पलीट करेगी ही, लेकिन क्या आज भारत सरकार इस नहर को कम्पलीट नहीं करवाना चाहती है, क्या भारत सरकार का इरादा इसको कम्पलीट करने का नहीं है ? (विघ्न) क्या भारत सरकार आज हम को पानी उपलब्ध नहीं करवाना चाहती है ? स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक डिस्पिलिंड पार्टी है । यह नहर कब से अधूरी पड़ी है ? तीनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है लेकिन फिर भी यह नहर नहीं बन रही है । डिस्पिलिन नाम की चीज क्या कहीं पर नजर आती है, क्या कांग्रेस पार्टी में कहीं पर कोई डिस्पिलिन है ? (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान चौधरी बंसी लाल जी अपने जमाने की बात भूल जाते हैं। एमरजैंसी के दिन थे, एमरजैंसी के ये खुद बड़े जबर-दस्त हीरो थे। एमरजैंसी लगवाने में भी यही हीरो थे। उस वक्त इनकी सैंटर में तूती चलती थी। उस वक्त यह नहर इन्होंने क्यों नहीं बनवा ली। उस वक्त भी पंजाब में तथा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि एमरजैंसी का हीरो बंसी लाल था लेकिन एमरजैंसी मैंने नहीं लगवाई थी। ये कहते हैं तो यह इनकी मर्जी है। (विघ्न) मुख्य मन्त्री जी को शायद एक बात याद नहीं रही, शायद ये भूल गए कि जब हम पावर में थे उस वक्त नहर बनवाने का कोई सवाल ही नहीं था। उस वक्त नहर बनवाने अथवा पानी दिलवाने में भारत सरकार नहीं थी। पहली बार यह मामला 24 मार्च, 1976 को आया और जब उस पर कार्यवाही करनी शुरू की गई तो चुनाव में जनता ने हमारी छुट्टी कर दी। (विघ्न) 1976-77 में मैं मुख्य मन्त्री नहीं था बल्कि उस समय मैं केन्द्र में रक्षा मन्त्री था। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उस वक्त काम चालू करने लगे थे लेकिन इलैक्शन हो गए और हमारी छुट्टी हो गई, 1977 से ले कर अब तक बहुत साल हो गए हैं। जब मैं 1986-87 में मुख्य मन्त्री बन कर आया तो मेरे वक्त में सबसे ज्यादा नहर का काम हुआ इस बारे में आप पंजाब की सी0ए0जी0 की रिपोर्ट देख सकते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा एस0वाई0एल0 का काम मेरे वक्त में हुआ था। (विघ्न एवं शोर)

प्रो0 छतर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरी आपसे गुजारिश है * * * * * * * *

Mr. Speaker : No point of order. (Noise & Interruptions). Nothing is to be recorded without my permission.

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं एक व्यवस्था की बात पर आता हूं। आपने जो रूलिंग दी कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उनकी बात को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। आप इस बारे में विचार करें।

श्री अध्यक्ष : उनकी कोई बात प्वायंट आफ आर्डर की नहीं थी। वह प्वायंट आफ आर्डर नहीं था।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप आर्टिकल 194 पढ़ें क्योंकि आप चाहें जिस चीज को कह देते हैं कि कार्यवाही से निकाल दिया जाए । आप कांस्टीच्यूशन का आर्टिकल 194 देखें जो इस प्रकार है—

194 :

Powers, privileges etc., of the House of Legislatures and of the members and committees thereof.

"Subject to the provisions of the Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State...."

इसके बाद हमारी असैम्बली का रूल 116 है । वह रूल कहता है कि—

"If the Speaker is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or un-parliamentary or undignified, he may, in his discretion order that such word or words be expunged from the proceedings of the Assembly."

अध्यक्ष महोदय, इसमें से कौन सी बात इस पर एप्लाई करती है जो आपने यह कह दिया कि एक्सपंज कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : जो बात वे कह रहे थे उसका कोई मायना नहीं था ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हम में से कोई भी आदमी हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन से ऊपर नहीं है । We are governed by the Rules of Procedure and Conduct of Business. We cannot go beyond that. आप जब यह समझते हैं कि हमारी बात ठीक नहीं है तो वह कार्यवाही से निकाल देते हैं ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी की तरह मैं अनपढ़ वकील तो नहीं हूं । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई आदमी प्वायंट आफ आर्डर उठाता है तो वह बाकायदा रूल का हवाला देकर उठाता है । अगर आप समझते हैं कि वह जो कह रहा है वह प्वायंट आफ आर्डर के तहत कह रहा है तो उसको रख सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि वह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है तो वह कार्यवाही से निकाल सकते हैं । (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है उस बारे में मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं। यह बात ठीक है कि if there is no point of order, if there is no substance in that point of order, then it should be disallowed. But it is not proper that that portion of point of order should not form part of the proceedings. You can very well say that it is no point of order. But it does not mean that it should go off the record. It should definitely form part of the proceedings (Noise & Interruptions).

बिजली मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, चौधरी बंसीलाल जी एस0 वाई0एल0 नहर के बारे में बोल रहे थे। इसी दौरान हमारे आनरेबल मैम्बर खड़े हुए और उन्होंने प्वायंट आफ आर्डर रेज किया लेकिन आपने उस प्वायंट आफ आर्डर को नहीं माना। अगर उसका सहारा लेकर कोई मैम्बर कुछ कहे when it does not constitute a point of order, how that portion of point of order will from part of the proceedings. फिर वह रिकार्ड पर कैसे आएगा ? वे अपने प्वायंट आफ आर्डर पर कुछ कहना चाहते थे लेकिन आपकी तरफ से यह रूलिंग आ गयी कि यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है तो फिर उनकी तरफ से कही गयी बातें रिकार्ड पर नहीं आ सकती हैं।

डा0 राम प्रकाश : स्पीकर साहब, एक बहुत ही अहम् मुद्दे पर बात चल रही है और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता के साथ ही लिया जाना चाहिए। यह जो रूल्ज आफ प्रोसिजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस इन दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली है इसके पृष्ठ 66 पर यह लिखा है कि—

(2) A point of order may be raised in relation to the Business before the House at the moment.

जो बात प्रोफैसर छतरपाल सिंह ने कही है वह इस संबंधित मुद्दे से ताल्लुक रखती है। अब मैं इसी रूल की प्रोवाइजो पढ़ता हूं—

> "Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of business before the House...." (Interruptions & Noise.)

Dr. Ram Parkash : Speaker, Sir, I may be allowed to read this rule. (Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : All right you read.

Dr. Ram Parkash : Sub-rule (3) of this rule is as under :—

> "(3) Subject to conditions referred to in sub-rule (1) and (2) a member may formulate a point of order and the

[Dr. Ram Parkash]

Speaker shall, decide whether the point raised is a point of order and if so, give the decision thereon, which shall be final...."

स्पीकर साहब, आप यह तो कह सकते हैं कि यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि उसको प्रोसीडिंग्ज से निकाला जाए। (विघ्न) स्पीकर साहब, या तो हाऊस को आप कंडक्ट कर लें या फिर चीफ मिनिस्टर साहब थोड़ी देर के लिए उस कुर्सी पर बैठ जाएं और इस हाउस को कंडक्ट कर लें। लेकिन हमें इस बात पर ऐतराज है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने फंक्शन के साथ-साथ स्पीकर के फंक्शंज भी करें और स्पीकर के पद की गरिमा को न मानें। मैं यह समझता हूं कि इस हाउस के जो स्पीकर साहब हैं वे इस हाउस के बिजनैस को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही लायक हैं। अगर कभी उन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी तो वे आपको बुला लेंगे। इसलिए आपको यहां से बैठे-बैठे उनको इशारे नहीं करने चाहिएं। स्पीकर साहब, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोफैसर छतर पाल सिंह ने जो अपनी बात कही है, उस पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या कोई मुख्य मन्त्री पुराने जमाने की बातों का हवाला देकर अपने दस साल की कारगुजारी जिसमें पानी का फैसला न होने वाली बात भी शामिल है, इस तरीके से इस प्वायंट को दबा सकता है? क्या वह इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? मैं समझता हूं कि अगर कोई सदस्य पानी जैसे मुद्दे के सवाल को उठाता है और यदि सरकार कानून का बहाना बनाकर उसके प्वायंट को रिकार्ड नहीं करवाने देती तो यह तो हरियाणा के लोगों की भावनाओं के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ होगी। आज पानी का मसला एक बड़ा मसला है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी आप बैठ जाइए।

डा0 राम प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इस नाते से कहना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण प्वाइंट पर अगर आप अपनी रूलिंग नहीं देना चाहते कि क्या चीफ मिनिस्टर पुराने जमाने की बातें कर सकते हैं या उन्हें अपना किरदार निभाना चाहिए? इसको हाउस की प्रोसीडिंग में से एक्सपंज करना कार्यवाही की किताब में नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, यह रूलिंग दी जा चुकी है कि यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने यह तो कह दिया कि यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है लेकिन the relovant portion quoted by Dr. Ram Parkash clearly says that if you find that this is not a point of order then you can very well say that it is not a point of order. Why it should not form part of the proceedings.

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आप बैठ जाइए । (शोर एवं व्यवधान) यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । अब बंसी लाल जी बोलेंगे ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, तीनों जगह केन्द्र में, हरियाणा में और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं । फिर भी हरियाणा सरकार भारत सरकार के खिलाफ जो कि मुख्य मन्त्री जी की पार्टी की ही सरकार है उसके बावजूद अदालत में गए हैं । इनके कायरेक्टिव्ज तो हरियाणा के लोगों को डैलीबरेट्ली मिसलीड करने के लिए और उनको पानी से वंचित करने के लिए हैं । इनका [एस0वाई0एल0 बनाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि अगर उस नहर को बनाने का इनका इरादा होता तो ये दिल्ली की सरकार से उसको बनवाते । इसी पैरा-16 में राज्यपाल महोदय ने कहा है—

> "Under the Haryana Water Resources Consolidation Project started in the State with World Bank assistance, effective steps are being taken for rehabilitation of the irrigation infrastructure, modernisation of the irrigation system and a better drainage system."

मैं समझता हूं कि यह बात करनी चाहिए, मैं यह बात करने के हक में हूं । मगर जिस ढंग से काम हो रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि स्टेट में पैसा कहां खर्च हो रहा है । मुझे यह नहीं पता लग रहा है कि पैसा कहां जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसके लिए आप हाउस की एक कमेटी बना दीजिए वह छान-बीन करके बताए कि पैसा प्रौपरली कैसे खर्च हो सकता है । आज की तारीख में रुपया ठीक से खर्च नहीं हो रहा है । ठीक से क्या खर्च होता, खर्च ही नहीं हो रहा है । हथनी कुंड बैराज की भी चर्चा हुई । राज्यपाल महोदय ने कह दिया कि यह 1999 तक बन जाएगा । अभी दो महीने पहले मैं हथनीकुंड बैराज पर हो कर आया हूं वहां कुछ भी काम नहीं हो रहा है । एक मजदूर भी वहां काम पर नहीं लगा हुआ है । वहां एक भी सीमेन्ट का कट्टा नहीं है । ईंट नहीं है । सरिया नहीं है । कोई काम वहां नहीं हो रहा है । मैं और 50-100 आदमी देखकर आए हैं । पैरा नं0 17 में राज्यपाल महोदय ने कहा है—

> "My Government has signed the power purchase agreement with the National Thermal Power Corporation for the gas-based 400 MW project at Faridabad. An agreement has also been reached with an Israeli Company regarding the draft power purchase agreement for the 700 MW thermal power plant at Yamunanagar."

अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के पिछले सैशन में मैंने कहा था कि 500 मैगावाट का एग्रीमैंट तो कम से कम एन0टी0पी0सी0 से कर लो । सरकार ने अच्छा किया कि

[चौधरी बंसी लाल]

चार सौ मैगावाट का उनसे एग्रीमैंट कर लिया । मैं कहता हूं कि 600 मैगावाट का और कर लो उससे स्टेट का फायदा है । इजराइल कम्पनी का भी जिक्र किया गया । क्योंकि बिजली बोर्ड की हालत ठीक नहीं है इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है आप बेशक प्राइवेट कम्पनियों को लाएं लेकिन इस सदन को सरकार प्रोग्रैस बताती रहे । सात सौ मैगावाट के बारे में भी मुख्य मन्त्री जी अपने जवाब में रोशनी डालें । मैं तो यह कहता हूं कि इससे भी ज्यादा काम और प्राइवेट कम्पनियों को दे दें क्योंकि पावर की पूर्ति करना स्टेट का फर्ज है । मैं इस बात से असहमत नहीं हूं कि यह काम प्राइवेट कम्पनियों से क्यों करवाया जा रहा है, आप जिससे मर्जी कराएं । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर कोई कम्पनी इजराइल की आ गई, अमरीका की आ गई, जापान की आ गई या कोरिया की आ गई तो उसके लिए मुझे एतराज नहीं है लेकिन एक बात है कि ये जो मल्टी नेशनल कम्पनियां आ रही हैं और ये कोई इंडस्ट्री या प्रोजैक्ट लगा रही हैं वे जब अपना मुनाफा वापिस ले जाने लगें तो वह कैश में न जाए बल्कि वे हिन्दुस्तान की बनी हुई कोई चीज ले जाएं ताकि हमारे देश को फायदा हो सके । अगर यहां से फारेन एक्सचेंज चला जाएगा तो देश का दीवाला निकल जाएगा । इसलिए अगर वे इस देश की बनी हुई कोई चीज ले कर जाएंगे तो उससे देश को फायदा होगा । हम इससे पहले भी गलती कर चुके हैं । इसलिए हमें उन पर यह पाबन्दी लगानी चाहिए कि आप मुनाफा ले जाएं लेकिन वह इन कैश नहीं, इन काइंड ले जाएं । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पैरा 23 हैल्थ के ऊपर है । इस पर मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूं कि कागजों पर चाहे कुछ भी लिखा हो या राज्यपाल महोदय के एड्रेस में लिखा हो लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में बहुत सी जगहों पर डिस्पैंसरीज नहीं हैं, अच्छे अस्पतालों की बिल्डिंग्ज नहीं हैं । जहां अस्पताल हैं वहां डाक्टर नहीं हैं । जहां डाक्टर हैं वहां दवाइयां नहीं हैं । इसका कारण यह है कि डाक्टर सरकारी नौकरी में कमाना चाहते हैं क्योंकि वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं । दूसरी बात यह है कि वे सिफारिश करवा कर अच्छी अच्छी जगहों पर जा कर बैठ जाते हैं । इस कारण से देहातों में डाक्टर नहीं मिलते । डाक्टर्ज की पोस्टें किसी भी अस्पताल में पूरी नहीं हैं इसलिए उनकी पोस्टें भरनी चाहिए । सभी जगहों पर डाक्टर होने चाहिएं और कम से कम गरीब आदमियों को दवाई भी मिलनी चाहिए । आज दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं कि तीन, चार रुपए से कम कोई गोली नहीं रही । इस वजह से गरीब आदमी अपना ईलाज नहीं करवा सकता । इसलिए उनको मुफ्त दवाई देने का प्रावधान किया जाए और दवाइयों के लिए हस्पतालों में जो पैसे की एलोकेशन की जाती है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, according to the population and according to the patients examined by the doctors in that Hospit l. बहुत से अस्पतालों में पेशेंट इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर डाक्टर नहीं हैं । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस चीज का पक्का प्रबन्ध करे ।

एक जो प्राइमरी एजूकेशन का प्रोग्राम है वह चार जिलों में शुरू किया जा रहा है। इस पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि इसका भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। आपको 160 करोड़ रुपए विश्व बैंक से नहीं लेने चाहिए थे बल्कि हरियाणा सरकार को अपने आप इसका प्रबन्ध करना चाहिए था। चार जिलों को तो आप वर्ल्ड बैंक से पैसा ले कर पढ़ा दोगे और बाकी जिलों का क्या होगा। इस बात के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वह अपने साधन से कार्यवाही करे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस सहमत हो तो हाउस का टाईम 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी। हाउस का टाईम 15 मिनट और बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : हाउस का टाईम 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पैरा नम्बर 25 में हरियाणा रोडवेज की बसिज की बहुत तारीफ की है और कहा है कि :—

> "......various road safety measures such as fixing of speed limit on National Highways, installation of speed regulators in State Roadways buses, providing information boards for road safety at important places and training as well as eye tests for drivers."

वैसे अगर सरकार का यह ईरादा है और इसको इम्पलीमैंट कर सकती है तो यह अच्छी बात है। मगर यह इम्पलीमैंट नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप हरियाणा प्रदेश की किसी सड़क पर निकल जाएं हर जगह हरियाणा रोडवेज की बसों का एक्सीडैंट हुआ मिलेगा। मेरे ख्याल में 2, 3, 4 या पांच से कम बसें हर रोज एक्सीडैंट से नहीं टूटती होंगी बल्कि रोजाना पांच से ज्यादा ही बसें एक्सीडैंट से टूटती होंगी इससे कम नहीं। हम सड़कों पर चलते हुए देखते हैं कि हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर सामने आने वाली गाड़ी को बचाने की कोशिश नहीं करता। किसी को बचना है तो वह बचे लेकिन वह किसी को बचाने की कोशिश नहीं करता। इस बारे में मैं

[चौधरी बंसी लाल]

आपके जरिए सरकार से कहूंगा कि सरकार हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्ज को 3-3 और 4-4 महीने के फासले से रिफ्रैशर कोर्स दिलवाए ताकि उनको गाड़ी ठीक ढंग से चलाने का और उसको ठीक ढंग से पार्क करने का ढंग आ जाए। जब सवारी उतारेंगे तो बस को सड़क के बीच में खड़ी कर देंगे। जब तक आप उनको रिफ्रैशर कोर्स नहीं दिलाएंगे उस वक्त तक पार नहीं पड़ेगी जो ड्राईवर्ज सरकार की बात नहीं मानते और रिफ्रैशर कोर्स के बाद भी गाड़ी ठीक ढंग से नहीं चलाते और अगर वे तीन सीरियस एक्सीडेंट कर देते हैं तो उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए।

चौधरी भजन लाल : आप इस अभिभाषण के कुछ पैरे छोड़ भी दें।

चौधरी बंसी लाल : मैंने इसके कई पैरे छोड़ दिए हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा जो पब्लिक इंट्रैस्ट में न हो। अध्यक्ष महोदय, अगर ये स्पीड लिमिट के मीटर्ज लगा देंगे तो यह बहुत अच्छी बात है। यह कोई खराब बात नहीं है। मैं एक चीज यह कहना चाहूंगा कि जितनी सड़कें हैं उन सब पर ट्रंक रूटस हैं इसलिए पर्टीकुलरली नेशनल हाई वेज पर रिकवरी वैन्ज रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि एक जगह किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वह सड़क के बीच में खड़ा है और तीन दिन के बाद जाएं तो फिर वही ट्रक वहीं पर खड़ा मिलता है। इस तरह से उसके कारण दूसरे ट्रैफिक के आने जाने में रूकावट पड़ती है और एक्सीडेंट का रेट भी बढ़ता है। तो रिकवरी वैन होगी तो वह वहां पर जाए और पुलिस वाले उस ट्रक को वहां से उठा कर एक तरफ डाल दें। उस ट्रक या कार का जो मालिक हो उससे पैसा वसूल कर लें। इसके अलावा मैं एक सुझाव यह भी दूंगा कि मोबाइल कोर्टस होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि सरकार इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से बात करके मोबाईल कोर्टस बनाए। मोबाईल कोर्टस बनने से यह होगा कि अगर पुलिस ने ड्राइवर का चालान कर दिया, अलबत्ता तो पुलिस वाले चालान नहीं करते जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे। एक जेब से हाथ इधर किया और उधर चले गए तो अगर मोबाईल कोर्टस होंगी तो वह वहीं खड़े खड़े जुर्माना कर देंगी। अगर किसी ड्राईवर का किसी पुलिस वाले ने चालान कर भी दिया तो वह अदालत में एहलमद से बात करके अपना लाईसैंस या कोई दूसरी चीज निकलवा लेगा और वह चालान भुगतने भी नहीं जाएगा इसलिए मोबाईल कोर्टस का बनाना बहुत ही जरूरी है जिनको समरी पावर्ज हों, वही इन एक्सीडैंटस को रोक सकते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसिज की हालत के बारे में जब मैंने आज से 8 या 10 महीने पहले अखबारों में यह पढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा रोडवेज की बसें नम्बर एक पर मानी गई हैं। यह पढ़ कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज की बसें आप सड़कों पर देख लें किसी का पीपा उखड़ा हुआ है, किसी की झाकी उखड़ी हुई है किसी का कुछ उखड़ा हुआ है और किसी का कुछ उखड़ा हुआ है। एक भी बस ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहूंगा कि पता नहीं मुख्य मंत्री

जी भिवानी जिले को पाकिस्तान में समझते हैं । भिवानी डिपो में जितनी भी बसें हैं सारी की सारी खराब हैं किसी बस की हालत ठीक नहीं है । कभी कभी आप उस डिपो में कोई अच्छी हालत की बस भी भेज दिया करो । खराब खराब बसें हमारे डिपो में भेज देते हैं और अच्छी अच्छी बसें दूसरी जगहों पर भेज देते हैं । मैं तो यह कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सारी बसें ठीक होनी चाहिए लेकिन बसों की हालत बहुत खस्ता है । सड़कों की क्वालिटी के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं । राज्यपाल महोदय ने कहा है कि पीने का पानी 40 लीटर प्रति व्यक्ति कर देंगे । पीने के पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरी अपनी कांस्टीच्यूंसी के कई गांव ऐसे हैं जिनमें पिछले 3-4 साल से पीने का पानी नहीं गया है । मेरी कांस्टीच्यूएंसी में रुण्डवा एक बहुत बड़ा गांव है । वहां पर पिछले 2-3 साल से पानी नहीं गया । इसी तरह से मीठी गांव है जिसको मुख्यमंत्री जी जानते हैं । लोहारु में एक मतानी गांव है, नौरंगाबाद गांव है और भी बहुत से गांव हैं जहां पर पिछले 3-4 साल से पीने का पानी नहीं गया है । जो सबसे पुरानी स्कीमें थी उनकी कैपेसिटी बढ़ाना तो दरकनार रहा उनमें पानी भी बिल्कुल ही नहीं जा रहा । पीने के पानी के बारे में मुझे एक बात याद आ गई । जब बाढ़ आई तो बाढ़ का पानी निकालने के लिए बलम्भा और मोखरा व दूसरे गांवों की हालत आंखों से देखी नहीं जा सकती थी, उनकी बहुत बुरी हालत थी । रोहतक जिले के बेरी हल्के में एक धराना गांव है । वहां के लोग बोट में बैठकर लैटरीन होने के लिए गांव से डेढ़ कि0 मी0 दूर जाते थे । उन गांवों के गंदे पानी को निकालने का प्रबंध जब सरकार ने किया तो वह पानी नहर में डाला गया । मैं पानी को नहर में डालने के बारे में कोई एतराज नहीं करता क्योंकि लोगों को बचाना था । बाढ़ को गए बहुत दिन हो गए मगर भिवानी शहर में आज भी पीने का पानी पोटेबल नहीं है । मैंने भिवानी से दिल्ली में दो बार पानी ले जाकर वहां पर लैबोरेटरी में टैस्ट करवाया है लेकिन वह पानी दोनों बार ही पीने के लिए फिट नहीं पाया गया । भिवानी शहर के पानी के बारे में तो मुझे व्यक्तिगत जानकारी है । इसके अलावा रोहतक है, मेहम है, दादरी है, हिसार भी है, इन सब के बारे में भी जांच कराई जानी चाहिए । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि एक मूविंग लैबोरेटरी भेजी जाये जो वाटर टैस्ट मौके पर ही करके बताये कि पानी ठीक है या नहीं । यह बहुत सीरियस मामला है । एक बात राज्यपाल महोदय ने पैरा 27 में कही है कि—

> "We are also considering to provide individual connections in these villages."

मैं यह नहीं कहता कि प्राईवेट कनैक्शन गांवों में लोगों को न दें । बड़ी खुशी से दें मुझे कोई एतराज नहीं है । मगर प्राईवेट कनैक्शन देने से पहले गांवों के पानी की ड्रेनेज का पूरा प्रबंध अवश्य करें । जब तक गांवों में ड्रेनेज का प्रबंध नहीं होगा तब तक गांवों की गलियों में कीचड़ फैल जायेगा और उनमें से निकलना मुश्किल हो जायेगा । बड़े-बड़े गांवों में पुराने वक्त की गलियां हैं वे तंग हैं, उनमें से निकलना

Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

[चौधरी बंसी लाल]

मुश्किल हो जाएगा । जब तक पानी की निकासी न हो, गली की ड्रेन ठीक न बने उस वक्त तक पानी के प्राइवेट कनैक्शंज देने से पहले सरकार को इस बारे में दो बार सोचना चाहिए । उसके बाद सरकार जहां ठीक समझे पीने के पानी के कनैक्शंज दे दे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं । इसके अलावा, जहां तक सीवरेज की बात है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक हरियाणा सरकार इन प्लास्टिक के लिफाफों पर पाबंदी नहीं लगाएगी तो अगले पांच साल में शायद ही किसी शहर की सीवरेज काम कर सकेगी, कोई भी नहीं करेगी ।

चौधरी भजन लाल : इस पर हरियाणा सरकार बैन नहीं लगा सकती ।

चौधरी बंसी लाल : अगर हरियाणा सरकार नहीं लगा सकती तो आप इस बारे में भारत सरकार से बात करें । सारे हिन्दुस्तान में प्लास्टिक के लिफाफों पर बैन लगाओ क्योंकि यह प्रोब्लम तो सब की है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक के लिफाफों पर बैन लगा दिया है तो उन्होंने कैसे लगा दिया । तो ये जो चीजें हैं इनको सरकार को देखना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, होडल, झज्जर, रोहतक, रिवाड़ी, कैथल आदि में पीने का पानी खराब है । कैथल में आधे शहर का पानी खराब है और आधे शहर का पानी ठीक है । उनको पानी ठीक से देना चाहिए और जहां पर ओलावृष्टि हुई है उनको जल्दी से जल्दी मुआविजा दिया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक आनरेबल मेम्बर ने कहा था कि हमारे यहां गन्ना बहुत होता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मन्त्री महोदय जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश से गन्ना इस प्रदेश में आ रहा है और अगर यू0 पी0 का गन्ना हमारे प्रदेश में आ रहा है तो यहां पर जो गन्ना इतना ज्यादा होता था वह कहां गया । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एम0 एल0 एज0 को 40-50 लाख रुपये अपनी कान्स्टीच्यूएंसीज़ में खर्च करने की बात है । मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि अगले दो तीन दिन में मुख्य मंत्री जी इसके आंकड़े मंगवा लें कितना कितना पैसा किस-किस एम0 एल0 ए0 के हल्के में खर्च किया गया है और कन्सर्ड एम0 एल0 ए0 ने किस काम पर उस पैसे को खर्च करवाया है, । यह सारी डिटेल ये हाउस में बता दें ताकि पता चल सके कि गवर्नमैंट किस हद तक अपनी बात पर कायम रहती है और कहां और कैसे पैसा खर्च किया गया है । अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । अब मैं अपनी बात को समाप्त करके अपना स्थान लेता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित किया जाता है ।

*13.41 बजे (तत्पश्चात सदन बुधवार, 28 फरवरी, 1996 प्रातः 9.30 बजे तक *स्थगित हुआ ।)